



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941

No. 310]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 4 सितम्बर, 2019

फा. सं. 6-1/2016-बीएंडसीएस.—केंद्र सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39, जो —

(ए) भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3 में दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (अ) और 45 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (vii) और (viii) और धारा 12 के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर और ऐसे ही अन्य सभी मामले संबंधी विनियम, 2019

(2019 की संख्या 02)

अध्याय—एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभण** — (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर और ऐसे ही अन्य सभी मामले संबंधी विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह विनियम पूरे देश में एट्रिसेबल प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रसारक, टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों तथा स्थानीय केबल आपरेटर द्वारा की जाने वाले सभी वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए प्रयोज्य होगा।

(3) (ए) उप खंड (बी) में अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर, यह विनियम सरकारी राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से एक सौ बीस दिन पश्चात् लागू होंगे।

(बी) विनियम 7 आधिकारिक राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. **परिभाषाएं** — (1) इन विनियमों में, जब तक की संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (ए) "अधिनियम" से आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) से है;
- (बी) "सक्रिय सब्सक्राइबर" से, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, आशय है कोई ऐसा सब्सक्राइबर, जिसे सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली के अनुसार टेलीविजन चैनलों के सिगनल प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और जिसके सेट टॉप बॉक्स को सिगनल मना नहीं किया गया है;
- (सी) "एड्रसेबल प्रणाली" से आशय है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (जिसमें हार्डवेयर और इससे सम्बद्ध सॉफ्टवेयर शामिल हैं) अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिन्हें एकीकृत प्रणाली में रखा गया हो और जिनके माध्यम से कार्यक्रमों का संचारण, टेलीविजन चैनलों के सिगनलों के पुनः संचारण समेत, कूट (एनक्रिप्टिड) किया जा सकता है और, जिन्हें सब्सक्राइबर को टेलीविजन चैनलों के वितरणों द्वारा सब्सक्राइबर की स्पष्ट पसंद व अनुरोध पर, प्राधिकृत सीमाओं के भीतर, सब्सक्राइबर के परिसर में किसी उपकरण अथवा उपकरणों से कूटानुवाद (डिकोड) किया जा सकता है;
- (डी) "अ-ला-कार्ट अथवा अ-ला-कार्ट चैनल" टीवी चैनल के प्रस्ताव के संदर्भ में से आशय एकल आधार वाले चैनल के अलग-अलग प्रस्ताव से है;
- (ई) "प्राधिकरण" से आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;
- (एफ) "औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार" से आशय दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट पद्धतियों से सक्रिय सब्सक्राइबर आधार की संख्या का औसत निकाल कर प्राप्त की गई संख्या से है;
- (जी) "बुके" या "चैनलों के बुके" से आशय विशिष्ट चैनलों के संकलन से है, जिनकी एक समूह या बंडल के रूप में पेशकश की जाती हैं और जिसमें इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताएं तथा संबद्ध अभिव्यक्तियों का तदनुसार आशय होगा;
- (एच) "प्रसारक" से आशय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, निगमित निकाय, या किसी संगठन या किसी ऐसे निकाय से है, जो अपने नाम पर अपने चैनलों के लिए केन्द्र सरकार से डॉउनलिकिंग अनुमति प्राप्त कर प्रोग्रामिंग सेवाएं मुहैया करवाता है;
- (आई) "अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रसारक की हिस्सेदारी" पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुके के संदर्भ में इसका आशय किसी टेलीविजन चैनलों के वितरण द्वारा प्रसारक को उसके पे चैनलों अथवा पे चैनलों के बुके के लिए, जैसा भी मामला हो, देय शुल्क है जिसके लिए उस प्रसारक से वितरण द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृति प्राप्त की गई हो;
- (जे) "प्रसारण सेवाओं" का आशय है अंतरिक्ष के माध्यम से अथवा केबल के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण द्वारा संचार के किसी भी रूप जैसे चिह्नों, सिग्नलों, लेखनों, चित्रों, प्रतिबिंबों और सभी प्रकार की आवाजों का प्रसार, जिसे आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना आशयित है, और इसकी सभी व्याकरणिक विभिन्नताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ माना जाएगा;
- (के) "केबल सेवा" अथवा "केबल टीवी सेवा" से आशय कार्यक्रमों का प्रसारण है, जिसमें केबल के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों का पुनःप्रसारण शामिल है;
- (एल) "केबल टेलीविजन नेटवर्क" अथवा "केबल टीवी नेटवर्क" से आशय है, क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ और संबन्धित सिगनल जनरेशन, नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिलकर बनी कोई प्रणाली, जिसे मल्टीपल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल सेवा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है;
- (एम) "कैरिज शुल्क" से आशय है, अन्य प्रसारकों के चैनलों की तुलना में प्रसारक के विभिन्न चैनलों का इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग मार्गदर्शिका में विशिष्ट स्थान का ब्योरा अथवा विशिष्ट चैनल संख्या का ब्योरा दिए बिना, टीवी चैनलों के वितरण के द्वारा संचालित प्लेटफार्म पर, उक्त प्रसारक के चैनल अथवा चैनलों के बुके (गुच्छों) के केवल कैरिज के लिए किसी प्रसारक द्वारा टीवी चैनलों के वितरण को देय शुल्क;
- (एन) "अनुपालन अधिकारी" से आशय है, किसी सेवा प्रदाता द्वारा नामजद कोई व्यक्ति जो इन विनियमों के तहत अनुपालन के लिए आवश्यकताओं को समझने में सक्षम है;
- (ओ) "डॉयरेक्ट-टू-होम ऑपरेटर" अथवा "डीटीएच ऑपरेटर" से आशय है ऐसा व्यक्ति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है;
- (पी) "डॉयरेक्ट-टू-होम सेवा" अथवा "डीटीएच सेवा" से आशय है उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके, बिना किसी मध्यस्थ, जैसे केबल आपरेटर अथवा टेलीविजन चैनलों के किसी अन्य वितरण, के सीधे सब्सक्राइबर के घर तक टेलीविजन के सिग्नलों का पुनःप्रसारण करना;
- (क्यू) "वितरण शुल्क" से आशय है, उपभोक्ताओं को, अपने पे टेलीविजन चैनल (चैनलों) या जनरल पे चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के वितरण के उद्देश्य के लिए टेलीविजन चैनलों के किसी वितरण को किसी प्रसारक द्वारा भुगतानयोग्य कोई शुल्क और इसमें कैरिज शुल्क शामिल नहीं हैं;
- (आर) "डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म" से आशय डीटीएच आपरेटर, मल्टी सिस्टम आपरेटर, एचआईटीएस आपरेटर अथवा आईपीटीवी आपरेटर के वितरण नेटवर्क से है;

- (एस) "टेलीविजन चैनलों का वितरक" अथवा "वितरक" से आशय डीटीएच आपरेटर, मल्टी सिस्टम आपरेटर, एचआईटीएस आपरेटर अथवा आईपीटीवी आपरेटर से है;
- (टी) "इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग मार्गदर्शिका" अथवा "ईपीजी" से आशय टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा अनुरक्षित कार्यक्रम मार्गदर्शिका से है जिसमें टेलीविजन चैनलों तथा कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जाता है और जिसमें कार्यक्रम और उनके समय निर्धारण संबंधी जानकारी होती है तथा इसमें ऐसी और जानकारी वाली मार्गदर्शिका शामिल होती है जिसमें सब्सक्राइबर नेवीगेट कर ऐसे उपलब्ध चैनलों और कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं;
- (यू) "फ्री-टु-एयर चैनल" अथवा "फ्री-टु-एयर टेलीविजन चैनल" से आशय ऐसे टेलीविजन चैनल से है, जिसे प्रसारक द्वारा इस रूप में घोषित किया जाता है और जिसके लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा ऐसे चैनल के सिग्नल हेतु प्रसारक को किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है;
- (वी) "हैड एंड इन द स्काई आपरेटर" अथवा "एचआईटीएस आपरेटर" से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा हैड एंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है;
- (डब्लू) "हैड एंड इन द स्काई सेवा" अथवा "एचआईटीएस सेवा" से आशय टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों के पुनर्प्रसारण सहित कार्यक्रमों के प्रसारण से है—
- (i) मध्यस्थों को जैसे केबल प्रचालक या मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को उपग्रह प्रणाली का प्रयोग करते हुए और सब्सक्राइबरों को सीधे नहीं; और
 - (ii) उपग्रह प्रणाली तथा स्वयं का केबल नेटवर्क उपयोग कर सब्सक्राइबरों को;
- (एक्स) "अंतःसंयोजन" से आशय है, ऐसे वाणिज्यिक और तकनीकी समझौते जिनके अंतर्गत सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबरों को प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने उपस्कर और नेटवर्क संयोजित करते हैं;
- (वाई) "अंतःसंयोजन करार" इसकी सभी व्याकरणिक भिन्नताओं और समझौते अभिव्यक्तियों के साथ इससे आशय है, ऐसे अंतःसंयोजन करार जिनमें टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों के वितरण के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों और निबंधनों का उपबंध किया गया है;
- (जेड) "अंतःसंयोजन विनियम" से आशय, दिनांक 03 मार्च, 2017 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एट्रिसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 से है;
- (एए) "इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन आपरेटर" अथवा "आईपीटीवी आपरेटर" से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा आईपीटीवी सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है;
- (बीबी) "इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा" अथवा "आईपीटीवी सेवा" से आशय है एक या अधिक सेवा प्रदाताओं के क्लोज्ड नेटवर्क पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके एट्रिसेबल पद्धति में मल्टी चैनल टेलीविजन कार्यक्रमों का वितरण करना;
- (सीसी) "स्थानीय केबल ऑपरेटर" अथवा "एलसीओ" से आशय, ऐसे व्यक्ति से है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 5 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है;
- (डीडी) "अधिकतम खुदरा मूल्य" अथवा "एमआरपी" से इस विनियम के प्रयोजनार्थ आशय, कर के अलावा, ऐसे अधिकतम मूल्य से है जो किसी सब्सक्राइबर द्वारा अ-ला-कार्ट पे चैनल अथवा पे-चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के लिए देय है;
- (ईई) "मल्टी सिस्टम ऑपरेटर" अथवा "एमएसओ" से आशय किसी ऐसे ऑपरेटर से है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11, के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया गया है और जो किसी प्रसारक से कोई कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और एक से अधिक सब्सक्राइबरों को सीधे ही अथवा एक या अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से, साथ-साथ प्राप्त करने के लिए, इन्हें पुनः संचारित करता है अथवा अपनी स्वयं की कार्यक्रम सेवा को संचारित करता है;
- (एफएफ) "पे प्रसारक" से आशय ऐसे प्रसारक से है, जिसने एक या एक से अधिक चैनलों को पे चैनल के रूप में, उपयुक्त विनियमों या टैरिफ आदेश के तहत, जैसा मामला हो, प्राधिकरण को घोषित किया है;
- (जीजी) "पे-चैनल" से आशय ऐसे चैनल से है, जिसे प्रसारक द्वारा इस रूप में घोषित किया जाता है तथा जिसके लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा प्रसारक को अधिकतम खुदरा मूल्य के हिस्से को भुगतान किया जाना होता है और जिसके लिए सब्सक्राइबरों तक ऐसे चैनलों के वितरण हेतु प्रसारक से विधिवत प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है;
- (एचएच) "कार्यक्रम" से आशय किसी टेलीविजन प्रसारण से है तथा इसमें निम्नवत शामिल हैं:—
- (i) फिल्मों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;
 - (ii) कोई श्रव्य अथवा दृश्य अथवा श्रव्य-दृश्य सजीव प्रदर्शन अथवा प्रस्तुतीकरण; और
- "कार्यक्रम सेवा" अभिव्यक्ति का तदनुसार अर्थ समझा जाएगा;
- (आईआई) "संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव" अथवा "आरआईओ" का आशय एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज से है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है, जिस पर अन्य सेवा प्रदाता ऐसे सेवा प्रदाता के साथ अंतःसंयोजन प्राप्त कर सकते हैं;

- (जेजे) "रजिस्टर" से आशय अंतःसंयोजन करारों और ऐसे ही अन्य सभी मामलों के रजिस्टर से है जिसे प्राधिकरण द्वारा उस स्वरूप में, जैसा समय-समय पर निर्णय लिया जाए, रखरखाव किया जाता है;
- (केके) "रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर" से आशय है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके संयुक्त उपक्रम(मों), यदि कोई हो तो, सहित संपूर्ण संवितरण नेटवर्क का औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार, वर्ष के मार्च माह में रिपोर्टिंग थ्रेशहोल्ड के समकक्ष अथवा उससे अधिक हो;
- (एलएल) "रिपोर्टिंग थ्रेशहोल्ड" से आशय है, एक लाख अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित निदेश अथवा आदेश द्वारा यथा विहित होगा;
- (एमएम) "सेट टॉप बाक्स" अथवा "एस.टी.बी." का आशय एक ऐसे उपकरण से है जो टेलीविजन रिसीवर से जुड़ा हुआ या उसका एक भाग होता है; और जो सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब किए गए चैनलों को देखने में समर्थ बनाता है;
- (एनएन) "सब्सक्राइबर" से आशय इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी टेलीविजन चैनल के वितरक द्वारा उपलब्ध कराई गई टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर बिना किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्प्रसारित किए केबल टेलीविजन के सिग्नल प्राप्त करता है और केबल टेलीविजन के सिग्नलों को आगे किसी अन्य व्यक्ति को कोई विशिष्ट धनराशि प्राप्त कर न ही सुनने देता है और न ही देखने देता है और सब्सक्राइबर की गई टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रत्येक स्थान पर अवस्थित ऐसा प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स एक सब्सक्राइबर माना जाएगा;(ओओ)
- (ओओ) "सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली" से आशय है, कोई प्रणाली या उपकरण जो सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब किए गए चैनल या चैनलों के बुके, प्रणाली में यथापरिभाषित चैनलों के बुके या चैनलों का मूल्य, किसी चैनल के बुके की एक्टिवेशन या डिएक्टिवेशन की तारीख और समय, सब्सक्राइबर के रिकार्ड पर किए गए सभी कार्यों का लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर को दिए गए इनवॉइस और भुगतान की गई धनराशि का प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में सब्सक्राइबर का रिकार्ड तथा ब्यौरा एकत्रित करता है;
- (पीपी) "टेलीविजन चैनल" से आशय किसी चैनल से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीतिगत दिशनिर्देशों के तहत डाउनलिकिंग हेतु अनुमति प्रदान की जाती गई हो तथा "चैनल" शब्द का अभिप्राय "टेलीविजन चैनल" माना जाएगा।

(2) इन विनियमों में इस्तेमाल किए गए परंतु परिभाषित न किए गए और अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों में परिभाषित सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों या नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, में उन्हें दिया गया है।

अध्याय-दो

सूचना प्रदान किए जाने की प्रक्रिया

3. प्रसारकों और वितरकों द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (रिफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर) और अंतःसंयोजन करार के संबंध में सूचना की रिपोर्टिंग—

- (1) प्रत्येक प्रसारक, अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से, अनुसूची-। में मुहैया कराए गए तरीके और प्रारूप के अनुसार या जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किसी निदेश या आदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो, के अनुसार, अपनी आरआईओ और उसके संशोधनों या आशोधनों के बारे में, अंतःसंयोजन विनियमावली के विनियम 7 के अनुसार अपनी वेबसाइट में प्रकाशन होने के साथ-साथ, प्राधिकरण को प्रतिवेदन करेगा।
- (2) प्रत्येक वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर), अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से, अनुसूची-।। में मुहैया कराए गए तरीके और प्रारूप के अनुसार या जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किसी निदेश या आदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो, के अनुसार, अपनी आरआईओ और उसके संशोधनों या आशोधनों के बारे में, अंतःसंयोजन विनियमावली के विनियम 8 के अनुसार अपनी वेबसाइट में प्रकाशन होने के साथ-साथ, प्राधिकरण को प्रतिवेदन करेगा।
- (3) प्रत्येक प्रसारक अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से, प्राधिकरण को चैनलों के संबंध में सभी अंतःसंयोजन करारों से संबंधित सूचना के बारे में प्राधिकरण को प्रतिवेदन करेगा
 - (i) जिनके लिए आरआईओ अंतःसंयोजन विनियमावली के विनियम 7 के अनुसार प्रकाशित किया गया है।
 - (ii) स्थापन के लिए,
 - (iii) विपणन के लिए, अथवा
 - (iv) अन्य किसी तकनीकी अथवा वाणिज्यिक करारों के लिए,

और इससे संबंधित आशोधनों और संशोधनों के संबंध में ऐसे समझौतों और संशोधनों व आशोधनों पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, तीन भागों में नामतः ए, बी और सी, उस 'रूप' और 'प्रारूप' में जो अनुसूची- III में दिया गया है अथवा किसी निदेश द्वारा अथवा समय-समय पर किसी आदेश प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, प्रदान करेगा।

बशर्त कि ऐसे सभी मौजूदा करारों जिन पर इन विनियमों के लागू होने की तिथि तक हस्ताक्षर हुए हैं, से संबंधित जानकारी इन विनियमों के लागू होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

(4) प्रत्येक रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से, सभी अंतःसंयोजन करारों से संबंधित सूचना की जानकारी प्राधिकरण को देगा, जिसके लिए आरआईओ को अंतःसंयोजन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार प्रकाशित किया गया है और जिसके संबंध में चैनलों के पुनर्प्रसारण हेतु प्रसारक से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर की तिथि से तीस दिनों के भीतर आशोधन अथवा संशोधन हुए हैं तथा ऐसे आशोधन अथवा संशोधन, जैसा भी मामला हो, उस 'रूप' और 'प्रारूप' में हुए हैं जो अनुसूची-IV में दी गई है अथवा किसी निदेश द्वारा अथवा समय-समय पर किसी आदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो।

बशर्ते कि ऐसे सभी मौजूदा करारों, जिन पर इन विनियमों के लागू होने की तिथि तक हस्ताक्षर हुए हैं, से संबंधित सूचना की जानकारी इन विनियमों के लागू होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

बशर्ते आगे कि, ऐसे मामलों में जहां संयुक्त उपक्रम(मों), यदि कोई हो, सहित किसी डिस्ट्रीब्यूटर, जो पिछले वर्ष में रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर था, के समग्र डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार रिपोर्टिंग की सीमा से कम हो, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर संबंधित वर्ष के मार्च के अंत से तीस दिनों के भीतर इस संबंध में प्राधिकरण को एक प्रमाणपत्र देगा जो उसके अनुपालन अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किया गया हो।

(5) प्रत्येक रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से सभी अंतःसंयोजन करारों तथा इससे जुड़े आशोधन अथवा संशोधन, जो एलसीओ के साथ हस्ताक्षरित हो, से संबंधित सूचना को ऐसे करारों के हस्ताक्षर होने तथा संशोधनों अथवा आशोधनों, जैसा भी मामला हो, की तिथि से तीस दिनों के भीतर अनुसूची-V में प्रदत्त 'रूप' और 'प्रारूप' में अथवा किसी निदेश के अनुसार प्राधिकार द्वारा अथवा समय-समय पर किसी आदेश द्वारा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

बशर्ते कि ऐसे सभी मौजूदा अंतःसंयोजन जिन पर इन विनियमों के लागू होने की तिथि तक हस्ताक्षर हुए हैं, से संबंधित सूचना की जानकारी इन विनियमों के लागू होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

(6) प्रत्येक रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से उप विनियम (3) के तहत प्रसारक और उसके बीच हस्ताक्षरित सभी अंतःसंयोजन करारों और इसमें किए गए आशोधनों अथवा संशोधनों के संबंध में प्रसारक द्वारा दर्ज करने की तिथि के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण के निदेश द्वारा निर्धारित तरीके से अथवा समय-समय पर किसी आदेश के अनुसार, प्रसारक द्वारा दी गई सूचना सत्यापन करेगा।

बशर्ते, यदि कोई प्रसारक ऐसे करारों और इसमें किए गए आशोधनों अथवा संशोधनों के संबंध में जानकारी प्रदान करने में असफल रहता है तो संबंधित रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर प्राधिकरण को ऐसे करारों और इसमें किए गए आशोधन अथवा संशोधन, जैसा भी मामला हो, हस्ताक्षर की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर इससे संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।

(7) प्रत्येक प्रसारक अपने अनुपालन अधिकारी के माध्यम से उप विनियम (4) के तहत उनके बीच हस्ताक्षरित सभी अंतःसंयोजन और इसमें किए गए आशोधनों अथवा संशोधनों के संबंध में रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दर्ज करने की तिथि के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण के निदेश द्वारा निर्धारित तरीके से अथवा समय-समय पर दिए गए आदेश के अनुसार, रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन करेगा।

बशर्ते, यदि कोई रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे करारों और इसमें किए गए आशोधनों अथवा संशोधनों के संबंध में जानकारी प्रदान करने में असफल रहता है तो संबंधित प्रसारक प्राधिकरण को ऐसे करारों और इसमें किए गए आशोधन अथवा संशोधन, जैसा भी मामला हो, हस्ताक्षर की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर इससे संबंधित सूचना प्रदान करेगा।

(8) प्रत्येक प्रसारक और रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, प्रत्येक वर्ष के मार्च के अंत से तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक प्रमाणपत्र भी जमा करेगा जो की उसके अनुपालन अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होगा, कि उसकी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सभी अंतःसंयोजन करारों और इसमें किए गए आशोधनों अथवा संशोधनों से संबंधित सभी अपेक्षित सूचनाओं, जिसे पिछले वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट किया जाना था, रिपोर्ट कर दिया गया और यह सूचना सही है, ठीक है तथा हर दृष्टिकोण से पूर्ण है।

4. प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सूचना देने अथवा दी गई सूचना की सत्यता की जांच करने में असफलता के परिणाम— (1) यदि कोई प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर नियत तिथि तक विनियम 3 के तहत यथा अपेक्षित सूचना देने अथवा प्रमाणपत्र देने अथवा दी गई सूचना का सत्यापन करने में असफल होता है तो वह अपने लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण की निबंधन व शर्तों अथवा अधिनियम अथवा नियमों अथवा विनियमों अथवा इसमें दिए गए आदेश अथवा इसके तहत जारी निदेश पर विपरीत प्रभाव डाले बिना नियत तिथि के बाद तीस दिनों तक चूक के लिए प्रतिदिन एक हजार रुपये की राशि और यदि यह चूक नियत तिथि से तीस दिनों के बाद भी जारी रहती है तो प्रतिदिन दो हजार रुपये की अतिरिक्त राशि, जिसे प्राधिकरण आदेश द्वारा निदेश दे, वित्तीय निरुत्साहन के रूप में देगा।

बशर्ते कि इस उप विनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्रभारित वित्तीय निरुत्साहन की राशि किसी भी स्थिति में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते आगे कि, यदि प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर को प्राधिकरण द्वारा दिए गए विनियमों के उल्लंघन, जो भी मामला हो, में अभ्यावेदन का उचित अवसर नहीं दिया तो प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के माध्यम से किसी राशि के भुगतान का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) इन विनियमों के तहत वित्तीय निरुत्साहन राशि के माध्यम से देय राशि को प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए खाता शीर्ष में विप्रेषित किया जाएगा।

अध्याय—तीन

रजिस्टर के रखरखाव की प्रक्रिया और इसका निरीक्षण

5. रजिस्टर का अनुरक्षण — प्राधिकरण रजिस्टर का अनुरक्षण दो भागों नामतः भाग—एक और भाग—दो में करेगा जहां:

(i) भाग— I में निम्नवत जानकारी होगी—

- (क) विनियम 3 के उप विनियम (1), (2), (4) और (5) के तहत प्रदान की गई जानकारी; और
- (ख) विनियम 3 के उप विनियम (3) के तहत भाग 'ए' में प्रदान की गई जानकारी;

(ii) भाग— II में विनियम 3 के उप विनियम (3) के तहत भाग 'बी' और 'सी' में दी गई जानकारी शामिल होगी।

6. रजिस्टर का निरीक्षण— (1) इस रजिस्टर को अगोपनीय माना जाएगा, जब तक किसी अंतःसंयोजन करार के लिए कोई पक्ष इसके तहत उप विनियम (2) में दिए गए अनुसार और निर्धारित प्रारूप में प्राधिकरण से भाग—दो में दर्ज समझौते के किसी भी भाग को गोपनीय रखने के लिए कोई अनुरोध नहीं करता है।

(2) उपर्युक्त उप विनियम (1) के अनुसार गोपनीयता का अनुरोध, गोपनीय रखे जाने वाले भाग के गैर-गोपनीय सारांश के साथ लिखित रूप में किया जाएगा। सेवा प्रदाता गोपनीय रखे जाने वाले पैराओं अथवा इनके भागों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेगा। इस अनुरोध के साथ ऐसी जानकारी को गोपनीय रखने के लिए कारण भी साथ होंगे।

(3) जहां प्राधिकरण गोपनीयता के अनुरोध को निरस्त करने का प्रस्ताव करेगा, वह सेवा प्रदाता को ऐसा करने के कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा और निर्धारित अवधि में इसे विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करेगा। ऐसे अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के विचारण पर प्राधिकरण अंतिम निर्णय लेगा। यदि प्राधिकरण सेवा प्रदाता का अनुरोध निरस्त करता है, तो वह लिखित रूप में ऐसा करने के कारणों सहित इसकी जानकारी प्रदान करेगा।

(4) उपर्युक्त उप विनियम (1) से (3) तक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्याधीन रजिस्टर का(के) गैर-गोपनीय भाग इसके अंतर्गत उप विनियम (7) के तहत निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी आम व्यक्ति हेतु जांच के लिए खुला रहेगा।

(5) इस रजिस्टर की जांच करने का इच्छुक कोई व्यक्ति लिखित रूप में मांगी गई जानकारी का ब्यौरा देते हुए प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामोदिदष्ट अधिकारी के पास आवेदन करेगा।

(6) यह नामोदिदष्ट अधिकारी इस रजिस्टर की जांच की अनुमति प्रदान करेगा और साथ ही इसके अंतर्गत उप विनियम (7) के तहत निर्धारित शुल्क की प्राप्ति पर रजिस्टर के संगत भाग के उद्घरण को उपलब्ध कराएगा।

(7) शुल्क और अन्य प्रशुल्कों का उद्ग्रहण;

- (i) इस रजिस्टर की जांच के लिए 50 रूपए प्रतिघंटा का शुल्क अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किसी निदेश अथवा किसी आदेश द्वारा यथा निर्धारित शुल्क प्रभारित किया जाएगा।
- (ii) इस रजिस्टर से उद्घरणों की प्रतियों के लिए 20 रूपए प्रति पृष्ठ अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किसी निदेश अथवा किसी आदेश द्वारा यथा निर्धारित शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

बशर्ते कि, प्राधिकरण उपर्युक्त वॉटरमार्क के साथ 'सॉफ्ट फार्मेट' में उद्घरण की प्रतियां प्रदान कर सकता है।

(8) इस विनियम में अंतर्निहित कुछ भी इस रजिस्टर में प्रविष्ट अंतःसंयोजन समझौते पर लागू नहीं होगा—

- (i) जिसके संबंध में ऐसे करारों की रिपोर्टिंग की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई हो, अथवा
- (ii) जिसके संबंध में इस करारों में यथा विनिर्दिष्ट वैधता अवधि समाप्त हो गई हो, इनमें से जो भी बाद में हो।

अध्याय—चार

विविध

7. अनुपालन अधिकारी की नामजदगी और उसके दायित्व — (1) प्रत्येक प्रसारक और डिस्ट्रीब्यूटर इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर एक अनुपालन अधिकारी को नामित करेगा।

(2) प्रत्येक प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर, जो इन विनियमों के प्रभावी होने के बाद अपना प्रचालन आरंभ करता है, अपने प्रचालन को आरंभ करने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर एक अनुपालन अधिकारी को नामित करेगा।

(3) प्रत्येक प्रसारक और डिस्ट्रीब्यूटर, इस विनियम के उपबंधों के तहत अनुपालन अधिकारी को नामित किए जाने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को निम्नवत की सत्यापित प्रति के साथ अनुपालन अधिकारी का नाम, पूरा पता, संपर्क संख्या और ईमेल पता का ब्यौरा प्रदान करेगा—

- (क) यदि सेवा प्रदाता कोई कंपनी है तो उस मामले में उसके बोर्ड का संकल्प; अथवा
- (ख) यदि सेवा प्रदाता कोई कंपनी नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी का प्राधिकार पत्र;

जिसमें अनुसूची VI में यथा उपबंधित ऐसे अनुपालन अधिकारी के पद को प्राधिकृत किया गया है:

(4) इस विनियम के उपबंधों के अंतर्गत नामजद किए गए अनुपालन अधिकारी के नाम में किसी परिवर्तन की स्थिति में, इसे बोर्ड के संकल्प या सक्षम अधिकारी से अधिकार पत्र, जैसा भी मामला हो, की अधिप्रमाणित प्रति के साथ-साथ, ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(5) अनुपालन अधिकारी के पते अथवा संपर्क नम्बर अथवा ई-मेल पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर इसकी सूचना ऐसे परिवर्तन के होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी।

(6) अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा—

(क) इन विनियमों और इन्हीं विनियमों के तहत जारी प्राधिकरण के निर्देशों के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करना; और

(ख) यह सुनिश्चित करना कि उचित प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं और इन विनियमों के अनुपालन के लिए इनका अनुसरण किया जा रहा है।

8. कठिनाइयों को दूर करना— इन विनियमों की व्याख्या अथवा इनके उपबंधों के अनुप्रयोग में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राधिकरण समय-समय पर उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

9. निरसन और व्यावृत्ति —(1) दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 के अंतःसंयोजन करार रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) विनियम, 2004 (2004 का 15) को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप विनियम (1) के तहत उल्लिखित विनियम के निरसन के बावजूद भी उक्त विनियम के तहत कुछ भी किया गया अथवा की गई कोई भी कार्यवाई अथवा प्रस्तावित कोई कार्यवाई इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के तहत की गई मानी जाएगी।

यू के श्रीवास्तव, सचिव प्रभारी

[विज्ञापन III/4/असा./197/19]

नोट: इसके साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन अंतःसंयोजन करार के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा रजिस्टर तथा ऐसे ही अन्य सभी मामले विनियम, 2019 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर और ऐसे ही अन्य सभी मामले संबंधी विनियम, 2019 (2019 की संख्या 02) के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (भादूविप्रा अधिनियम) प्राधिकरण को अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगति और प्रभावी अंतर्संयोजना को सुनिश्चित करने, अंतर्संयोजना की निबंधन और शर्तों को निर्धारित करने तथा अपने राजस्वों की हिस्सेदारी के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था को विनियमित करने का कार्य सौंपता है। अधिसूचना संख्या 2004 का 39 [(सा. आ. 44 (इ.) और 45 (इ.)] के तहत वर्ष 2004 में भारतीय दूरसंचार अधिनियम, 1997 की धारा 2(के) की शर्तों के तहत दूरसंचार सेवा के दायरे में प्रसारण और केबल सेवाओं को लाया गया था।
2. सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन एक तकनीकी अथवा वाणिज्यिक अथवा तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवस्था का संयोजन है जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता अपने उपकरण और नेटवर्कों को जोड़ता है ताकि सब्सक्राइबर सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके। तदनुसार, प्राधिकरण ने दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवा) अंतःसंयोजन विनियम, 2004 तथा दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवा) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणालियाँ) विनियम, 2012 तैयार कर अंतःसंयोजन के लिए एक विनियामक रूपरेखा लागू की थी। इस रूपरेखा के आधार पर टेलीविजन चैनलों के प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर एक समझौता करने के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप प्रदान करते हैं। मौजूदा अंतःसंयोजन विनियामक ढांचा के तहत प्रसारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे गैर-विभेदकारी शर्तों पर टीवी चैनलों के सिग्नल टीवी चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रदान करें। इसी प्रकार, टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे गैर-विभेदकारी शर्तों पर प्रसारकों को अपने नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करें।
3. भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (बी) प्राधिकरण को अंतःसंयोजन करारों की रजिस्टर को अनुरक्षित रखने तथा जांच के लिए इसे तैयार रखने का अधिदेश प्रदान करता है। इन उपबंधों को नीचे पुनः उद्धृत किया गया है:

“ 11 (1) (बी) -----

vii. अंतःसंयोजन करार और इन विनियमों में प्रदत्त अन्य सभी ऐसे मामलों से संबंधित रजिस्टर का अनुरक्षण;

viii. इन विनियमों में यथा प्रदत्त ऐसे शुल्क के भुगतान तथा ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन पर किसी भी सामान्य व्यक्ति हेतु जांच के लिए खंड (7) के तहत अनुरक्षित रजिस्टर को दिखाना;

ix. ----- ”

4. भादूविप्रा अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों तथा अंतःसंयोजन के लिए विनियामक ढांचे को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 को पृथक विनियमों को अधिसूचित किया नामतः “ अंतःसंयोजन करार रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवाएं) विनियम, 2004 ” (2004 का 15) (जिसे इसके पश्चात् अंतःसंयोजन विनियम रजिस्टर कहा जाएगा) जिसमें प्रसारण और केबल सेवाओं हेतु अंतःसंयोजन करारों के रजिस्टर की पद्धतियों का निर्धारण किया गया है। उक्त विनियमों को अंतःसंयोजन विनियमों में होने वाले बदलाव की तर्ज पर समय-समय पर संशोधन किए गए।

5. अंतःसंयोजन विनियम रजिस्टर के अनुसार प्रसारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक आधार पर टीवी चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ हुए अंतःसंयोजन करारों का ब्यौरा दें। उसी प्रकार, डीटीएच आपरेटरों, एचआईटीएस आपरेटरों और आईपीटीवी आपरेटरों से अपेक्षा थी कि वे वार्षिक आधार पर प्रसारक के साथ हुए अपने अंतःसंयोजन समझौतों की रिपोर्ट दें। प्रसारकों को दिनांक 29 जुलाई, 2009 को एक निदेश जारी किया गया जिसमें उन्हें अंतःसंयोजन समझौते के मुद्रित रूप के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप ('नॉन-राइटबल सीडी') में ब्यौरा देने का निदेश दिया गया। प्राधिकरण को प्रत्येक अंतःसंयोजन करारों की प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतःसंयोजन करारों का ब्यौरा देने के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2009 को डीटीएच, एचआईटीएस और आईपीटीवी आपरेटर को एक निदेश जारी किया गया। अंतःसंयोजन समझौते की रजिस्टर को दो भागों: भाग क और भाग ख में अनुरक्षित रखा जाना था जिसमें भाग क को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी आम व्यक्ति को जांच के लिए दिखाया जाएगा और भाग-ख को व्यक्तियों द्वारा जांच किए जाने के लिए खुला नहीं रखा गया। भाग-ख में ऐसी सूचना अंतर्विष्ट थी जिसे सेवा प्रदाता के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा गोपनीय रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त सूचना की गोपनीयता का निर्णय करते समय प्राधिकरण के लिए भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (जानकारी तक पहुंच) विनियम, 2005 के संगत प्रावधानों का अनुसरण करना आवश्यक था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जानकारी तक पहुंच) विनियम, 2005 में निम्नलिखित सूचना के प्रकटन से छूट का एक उपबंध है:
- (i) व्यापार और वाणिज्यिक गोपनीयता और कानून द्वारा संरक्षित सूचना;
 - (ii) वाणिज्यिक और वित्तीय रूप से संवेदनशील जानकारी, जिसके प्रकटन से सेवा प्रदाताओं को अनुचित लाभ या अनुचित हानि होने की संभावना हो, अथवा उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के साथ समझौता होता हो।
6. रजिस्टर विनियम, 2004 के अंतर्गत टेलीविजन चैनलों के प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दर्ज अंतःसंयोजन/ दिए गए ब्योरे की जांच के संबंध में प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि:
- क) टेलीविजन चैनलों के विभिन्न प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त फॉइलिंग में एकरूपता की कमी थी;
 - ख) मानक सहबद्धता समझौते की फाइलिंग के संबंध में रजिस्टर विनियम, 2004 में अपेक्षा की विभिन्न व्याख्या थी;
 - ग) मुद्रित रूप में सूचना की रिपोर्टिंग एक समय लेने वाला और श्रमसाध्य कार्य बन गया था और यह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं था। इसलिए, रजिस्टर विनियम, 2004 की समीक्षा व्यावहारिक की गई है।
7. अंतःसंयोजन समझौतों के रजिस्टर हेतु विनियामक रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए सुस्थापित पद्धतियों की तर्ज पर प्राधिकरण ने दिनांक 23 मार्च, 2016 को " अंतःसंयोजन करार रजिस्टर (प्रसारण और केबल सेवा) विनियम, 2016" शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया। उक्त परामर्श पत्र के उत्तर में हितधारकों से कुल 26 टिप्पणियां और 2 प्रति टिप्पणियां प्राप्त हुईं। बाद में दिनांक 26 मई, 2016 को दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में हितधारकों ने भाग लिया।
8. इस दौरान, प्राधिकरण ने दिनांक 03 मार्च, 2017 को एक नया विनियामक ढांचा अधिसूचित किया जो सभी प्रकार के एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए एकसमान है। उक्त रूपरेखा में निम्नलिखित विनियम और प्रशुल्क की व्यवस्था है:
- क. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (इसके पश्चात् इसे अंतःसंयोजन विनियम, 2017 कहा जाएगा)।
 - ख. गुणवत्तापूर्ण सेवा का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (इसके पश्चात् इसे क्यूओएस विनियम, 2017 कहा जाएगा)।
 - ग. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क व्यवस्था, 2017 (इसके पश्चात् इसे प्रशुल्क व्यवस्था, 2017 कहा जाएगा)।
9. इस नए विनियामक ढांचे को मार्च, 2017 को अधिसूचित किया गया था। तथापि, उक्त विनियमों की कानूनी चुनौती दिए जाने के कारण यह विनियम दिनांक 03 जुलाई, 2018 को विधिक मुद्दों के समाधान के बाद प्रभावी हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसके पश्चात् दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के अपने आदेश के तहत भादूविप्रा के अधिकारों को बनाए रखा और यह निर्णय दिया कि विनियम और प्रशुल्क व्यवस्था भादूविप्रा अधिनियम के शक्ति के अधीन है। कुछ सेवा प्रदाताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इन विनियमों और प्रशुल्क व्यवस्था को चुनौती भी दी है। नए विनियामक ढांचे के प्रभावी होने के बाद सभी सेवा प्रदाताओं से अपेक्षित है कि वे उक्त रूपरेखा के अनुसार अंतःसंयोजन करार करें; परिणामस्वरूप इन विनियमों के तहत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं नई रूपरेखा द्वारा निर्धारित मानकों पर निर्भर हैं। इस नई विनियामक ढांचा की मुख्य विशेषताएं निम्नवत रूप में दी गई हैं:
- क) प्रत्येक प्रसारक के लिए यह अपेक्षित है कि अलाकार्ड आधार पर अपने पे चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की घोषणा करें। तथापि, यह अधिकतम खुदरा मूल्य सभी प्रकार के एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए एक समान होंगे।
 - ख) प्रत्येक प्रसारक को पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य के न्यूनतम 20 प्रतिशत पर वितरण शुल्क जो 35 प्रतिशत तक हो सकता है, की घोषणा करनी चाहिए।
 - ग) वितरण शुल्क के अतिरिक्त, प्रसारक, डिस्ट्रीब्यूटरों को छूट की पेशकश कर सकते हैं, जो पे चैनलों अथवा पे चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। तथापि, किसी भी स्थिति में किसी प्रसारक द्वारा घोषित वितरण शुल्क और पेशकश की गई छूट का योग पे चैनल अथवा पे चैनलों के बुके, जैसा भी मामला हो, के अधिकतम खुदरा मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।

- घ) प्रत्येक प्रसारक को अपने वेबसाइट पर रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर (आरआईओ) प्रकाशित करना चाहिए जिसमें अपने पे चैनलों और पे चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य, वितरण शुल्क, छूट आदि की जानकारी हो और साथ ही साथ इसकी एक प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी चाहिए।
- ड.) प्रत्येक प्रसारक के लिए यह अपेक्षित है कि वह टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर को पे चैनलों का सिग्नल देने के लिए उसके द्वारा प्रकाशित आरआईओ के आधार पर एक लिखित अंतःसंयोजन करार करे।
- च) उसी प्रकार, टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यह अपेक्षित है कि अपने वितरण नेटवर्क पर चैनल को वहन करने के लिए अपनी वेबसाइट पर आरआईओ को प्रकाशित करे। ऐसे आरआईओ में टारगेट मार्केट, वाहक शुल्क दर, वाहक शुल्क की गणना पद्धति आदि जैसी सूचना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और साथ ही साथ प्राधिकरण को एक प्रति भी प्रदान करनी चाहिए।
- छ) वाहक शुल्क की दर की उच्चतम सीमा को 0.20 रुपए प्रति स्टैंडर्ड डेफिनिशन चैनल और 0.40 रुपए प्रति हाई डेफिनिशन चैनल तक रखी गई है। वाहक शुल्क संगणना की पद्धति इन विनियमों में ही निर्धारित है। डिस्ट्रीब्यूटर वाहक शुल्क के संबंध में छूट पेशकश कर सकता है। तथापि, इस प्रकार की छूट 35 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।
- ज) प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपेक्षित है कि वह टेलीविजन चैनलों को चलाने के लिए प्रसारक के साथ अपने प्रकाशित आरआईओ के आधार पर एक लिखित समझौता करे जिसके संबंध में ऐसे प्रसारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
- झ) दो सेवा प्रदाताओं के बीच किसी चैनल के लिए किसी अन्य प्रकार का शुल्क यथा विपणन शुल्क, स्थापन शुल्क आदि का भुगतान अंतःसंयोजन करार के अनुसार किया जाना चाहिए और इसकी सूचना प्राधिकरण को दी जानी चाहिए।
- ञ) कुछ डिस्ट्रीब्यूटर (उदाहरण के लिए मल्टी सिस्टम आपरेटर) एलसीओ के माध्यम से प्रसारण सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए यह अनिवार्य है कि सिग्नल प्रदान करने से पूर्व लिखित करार करें। ऐसे अंतःसंयोजन समझौते में प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित मॉडल अंतःसंयोजन करार (एमआईए)/ मानक अंतःसंयोजन करार (एसआईए) के अनुसार मानक उपबंधों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: उपर्युक्त मुख्य बिंदु केवल सामान्य व्याख्या के लिए हैं और इनका इन विनियमों में संगत खंड(डों) के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10. इस परामर्श प्रक्रिया में प्राप्त टिप्पणियों और नए विनियामक ढांचे के कार्यान्वयन के अनुसरण में बाजार में घटनाक्रमों के विश्लेषण के आधार पर अंतःसंयोजन करार विनियम के प्रारूप दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा रजिस्टर, 2019 को दिनांक 22 अप्रैल, 2019 को भारतीय दूरसंचार वि. नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। सभी हितधारियों से इन प्रारूप विनियमों पर दिनांक 06 मई, 2019 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। कुछ हितधारियों द्वारा किए गए अनुरोधों के मद्देनजर लिखित टिप्पणियों को देने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर दिनांक 13 मई, 2019 कर दिया गया और दिनांक 20 मई, 2019 तक प्रति टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। उपर्युक्त परामर्श पत्र के उत्तर में हितधारियों से कुल 21 टिप्पणियां प्राप्त हुईं। बाद में, दिल्ली में दिनांक 10 जून, 2019 एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में हितधारियों ने इस खुला मंच चर्चा में भाग लिया।
11. निम्नलिखित पैराओं में इन मुद्दों पर हितधारियों से प्राप्त टिप्पणियों/ विचारों का सार, इन टिप्पणियों का विश्लेषण और इन विनियमों के उद्देश्य और कारण दिए गए हैं।

अंतःसंयोजन करारों के संबंध में जानकारी संबंधी अपेक्षाएं

12. टेलीविजन चैनलों के वितरण के 'वेल्यू चेन' में प्रसारक, टेलीविजन चैनल, स्थानीय केबल आपरेटर और अंतिम सब्सक्राइबर शामिल हैं। प्रसारक से सब्सक्राइबर तक टेलीविजन चैनलों के वितरण के कारोबार में दो स्तर हैं — i) प्रसारक टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर को टेलीविजन चैनल के सिग्नल प्रदान करता है और ii) टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर सब्सक्राइबरों को या तो सीधे या स्थानीय केबल आपरेटरों के माध्यम से इन चैनल मुहैया कराता है। टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों में डीटीएच आपरेटर सब्सक्राइबर को सीधे सेवा मुहैया कराता है जबकि, एमएसओ और एचआईटीएस आपरेटर सामान्यतया अपने लिंक वाले एलसीओ के माध्यम से सब्सक्राइबरों को सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार, टेलीविजन चैनलों के प्रावधान की कारोबारी प्रक्रिया में टेलीविजन सिग्नल टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से सब्सक्राइबरों को प्रसारकों से टेलीविजन सिग्नल प्रवाह प्राप्त होता है। तथापि, इस 'वेल्यू चेन' में टेलीविजन चैनल का प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर प्राप्तकर्ता अथवा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब डिस्ट्रीब्यूटर को प्रसारक से टेलीविजन चैनलों के सिग्नल की आवश्यकता होती है तो यह एक प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य करता है और ऐसे मामले में प्रसारक टेलीविजन चैनल के सिग्नल का प्रदाता बन जाता है। इसी प्रकार, जब प्रसारक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने नेटवर्क पर उनके टेलीविजन चैनल प्रदान करने के अनुरोध के साथ पहुंच बनाता है तो यह एक प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य करता है और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पहुंच का एक प्रदाता बन जाता है।
13. इसलिए, परामर्श पत्र में यह परिकल्पना की गई कि टेलीविजन सिग्नल का प्रदाता अथवा नेटवर्क तक पहुंच, जैसा भी मामला हो, को प्राधिकरण के लिए अंतःसंयोजन करारों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। तदनुसार, परामर्श पत्र में यह प्रस्ताव किया गया था कि पे चैनल के प्रसारक और टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर के बीच अंतःसंयोजन करारों का ब्योरे की जानकारी पे चैनल के प्रसारक द्वारा दी जाएगी। इस प्रकार, डिस्ट्रीब्यूटर और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन ब्योरे की सूचना डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं भी लागू हो, डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा वाहक संबंधी ब्योरे की जानकारी प्रदान की जाएगी।
14. अंतःसंयोजन विनियम 7 के अनुसार प्रत्येक प्रसारक के लिए रिकार्ड करने के उद्देश्य से अपने आरआईओ की प्रति को प्राधिकरण को देना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, इसमें किसी भी प्रकार के संशोधनों की सूचना अंतःसंयोजन विनियम के उप खंड 7(8) के अनुसार दिया जाना होता है। अंतःसंयोजन विनियम 8 के अनुसार टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को रिकार्ड के प्रयोजनार्थ अपने आरआईओ की एक प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, इसमें किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी अंतःसंयोजन विनियम के उपखंड 8(7)

के अनुसार देनी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर के आकार के अनपेक्षित, सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने आरआईओ संबंधी जानकारी प्रदान करना अपेक्षित होता है।

15. परामर्श प्रक्रिया के दौरान एक हितधारी ने यह टिप्पणी की कि वाहक शुल्क/स्थापन शुल्क समझौता, अंतःसंयोजन करार नहीं है। इसलिए, वाहक शुल्क/स्थापन शुल्क की सूचना देने के लिए कोई भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कुछ हितधारकों ने यह टिप्पणी की कि पूर्ण परामर्श और भेदभाव रहित सेवा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पक्षों को किसी भी क्षतिपूर्ति (मौद्रिक संदर्भ या अन्यथा¹) सहित सभी समझौतों को प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाना चाहिए कि चाहे उनके बीच वाहक/विपणन/सहायता अथवा अन्य टैग पर हस्ताक्षर हुए हों। प्रारूप विनियम से सं. बंधित परामर्श प्रक्रिया के दौरान कई हितधारियों ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रारूप विनियमों के तहत जानकारी संबंधी अपेक्षाएं केवल सब्सक्रिप्शन, वाहक/आरआईओ स्थापन तक सीमित रहनी चाहिए। प्रसारकों और डीपीओ के बीच किसी अन्य वाणिज्यिक समझौतों के समावेश से इन विनियमों के कार्यक्षेत्र विस्तार होगा। कुछ हितधारकों ने इस बात का पक्ष लिया कि टेलीविजन चैनलों के प्रसारक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हस्ताक्षरित विपणन अथवा सहायता अथवा दृश्यता अथवा स्थापन के लिए किसी प्रोत्साहन (मौद्रिक या अन्यथा) सहित सभी समझौतों के ब्योरे की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। कुछ हितधारकों ने यह बताया है कि स्थापन के समझौते जिन पर कोई रोक टोक नहीं है, सारे नियमों को विदूषित कर रहे हैं। उनके अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर प्राप्त लचीलेपन का दुरुपयोग कर प्रसारकों को परेशान कर रहे हैं। एक हितधारी ने यह भी विचार दिया कि किसी प्रसारक के लिए समान कार्य अवसर को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भिन्न प्रसारकों से भिन्न विपणन शुल्कों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता होती है अथवा वह कतिपय प्रसारकों को इसकी छूट दे सकता है। यह इस नई व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन है जिस व्यवस्था का लक्ष्य समान अवसर सृजित करना, उचित और भेदभाव रहित पद्धति प्रदान करना है।
16. 'अंतःसंयोजन करार' की परिभाषा (क्लॉज 2 (y)) में सेवा प्रदाताओं के बीच सभी तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसलिए इस विनियम के दायरे और शासनादेश में टेलिविजन चैनलों के पुनः प्रसारण के लिए सभी तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 11(1) (बी) (vii) में प्राधिकरण को यह अधिदेशित है कि वह अंतःसंयोजन करार के रजिस्टर को अधुण्ण रखे और **अन्य सभी ऐसे मामले** जो इन विनियमों में प्रदान किया जा सके। अंतःसंयोजन विनियम और यह विनियम गैर पक्षपात पूर्ण सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी शासन बनाने का प्रयास करता है। विनियम में सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं। विनियम सेवा प्रदाताओं को व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी की गोपनीयता का दावा करने का अवसर प्रदान करता है। रेगुलेटर द्वारा जानकारी मांगना किसी भी तरह से मार्केट पारटिसिपेंट की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाता है। अधिनियम प्राधिकरण को सभी तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवस्था सहित किसी भी जानकारी के लिए मांगने का अधिकार देता है।
17. अंतःसंयोजन विनियम का मुख्य सिद्धांत पारदर्शिता और भेदभाव नहीं करना है। सेवा प्रदाताओं के बीच सभी परिणामी करारों (अंतःसंयोजन करारों के परिणामी) में पारदर्शिता और गैर-भेदभाव के सिद्धांत का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस तरह के उत्तरगामी करारों द्वारा परस्पर संबंधों के अनिवार्य तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूप को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। इन समझौतों की तुलना में (स्थापन शुल्क, विपणन शुल्क अथवा सेवा प्रदाताओं के बीच परस्पर समझौते के किसी अन्य नाम) के संदर्भ में प्राधिकरण ने कम नियंत्रण वाली विनियामक व्यवस्था के सिद्धांत का अनुसरण किया जहां कोई भी उच्चतम सीमा अथवा सूत्र निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, क्षेत्र विनियामक के रूप में प्राधिकरण के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह प्रभावी निरीक्षण के लिए ऐसी व्यवस्थाओं/समझौतों के प्रकार और वाणिज्यिक अंतर्प्रस्तुता से अवगत हों। सेवा प्रदाता ऐसे करार(रों) पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं; तथापि, इसकी जानकारी विनियामक को दी जानी चाहिए।
18. अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के अनुसार प्रसारक के लिए पे चैनलों के सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूटरों को देने के पूर्व एक लिखित अंतःसंयोजन करार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि पे चैनलों के संबंध में जानकारी देने का दायित्व पे प्रसारकों पर होगा क्योंकि ऐसे मामले में वह सिग्नल प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के संदर्भ में टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रसारक के साथ एक लिखित समझौता करे जहां प्रसारक ने डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के संबंध में अपने टेलीविजन चैनलों को चलाने का अनुरोध किया है। इसलिए, ऐसे मामलों में इस नेटवर्क के एक्सेस प्रदाता के रूप में ऐसे समझौते से संबंधित जानकारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर और एलसीओ के बीच अंतःसंयोजन करारों के मामले में जहां कहीं भी प्रयोज्य हो, यह जानकारी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रदान की जाएगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर उक्त एलसीओ को सिग्नल का प्रदाता होता है। तदनुसार, इन विनियमों में अनिवार्य उपबंध शामिल किए गए हैं।
19. जहां तक स्थापन समझौते का संबंध है, प्राधिकरण ने नोट किया कि मौजूदा विनियामक ढांचे के अनुसार ईपीजी में अपेक्षित स्थिति में चैनल के स्थापन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रसारक निर्धारित सीमा के भीतर छूट प्रदान कर सकता है अथवा आपस में सहमत हुए शुल्क का भुगतान कर सकता है। यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्राधिकरण के पास ऐसे समझौते अथवा अन्य कोई व्यक्तिगत समझौतों को जमा करने की आवश्यकता है। प्राधिकरण का विचार है कि अन्य सभी व्यक्तिगत समझौतों का ब्योरा जिसमें विपणन, स्थापन, विज्ञापन स्लॉट संबंधी समझौता, विस्तारित ऋण सुविधा आदि शामिल है, की जानकारी प्रसारकों द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, प्रसारक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच विपणन शुल्क ब्योरा और इस मामले में किसी चैनल के लिए किसी प्रकार के शुल्क की जानकारी प्राधिकरण को दी जाएगी। इस प्रकार, टेलीविजन चैनलों के प्रसारक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हस्ताक्षर किए गए विपणन अथवा सहायता अथवा दृश्यता अथवा स्थापन के लिए किसी भी प्रोत्साहन (मौद्रिक अथवा अन्यथा) की जानकारी प्रसारक द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी।
20. अपने आरआईओ की जानकारी देने के अतिरिक्त, प्रसारक आरआईओ के अनुसार टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हस्ताक्षर किए गए व्यक्तिगत समझौतों की जानकारी का ब्योरा भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रसारक टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हस्ताक्षरित अन्य सभी व्यक्तिगत समझौतों के ब्योरों की भी जानकारी देगा। आरआईओ आधारित समझौतों में किसी प्रकार के विचलन की जानकारी, इस वि. नियम के विनियम 3(3) के तहत दिए जाने की भी आवश्यकता होगी। तदनुसार, इन विनियमों में अनिवार्य उपबंध शामिल किए गए हैं।

¹ उदाहरण के लिए: कोई करार जिसमें कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हों, परंतु जिसमें आश्वस्त रूप से विज्ञापन के स्लॉट अथवा आश्वस्त रूप से एलसीएन नम्बर आदि मुहैया कराए गए हों

21. प्रारूप विनियमों में यह विहित करते हैं कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रैसेबल प्रणालियाँ) के उपबंधों के अनुरूप विनिर्दिष्ट अनुपालन अधिकारी को अंतःसंयोजन करार, रजिस्टर विनियमों के तहत भी अनुपालन अधिकारी को नामित किया था। प्रारूप विनियमों के संबंध में परामर्श के दौरान कुछ हितधारकों ने यह टिप्पणी की कि उनके संगठनात्मक ढांचे को देखते हुए अन्य विनियमों के तहत विनियामक अनुपालन अधिकारी अंतःसंयोजन करारों संबंधी कार्यवाही नहीं करता है, इसलिए, इन हितधारकों ने टिप्पणी की कि सेवा प्रदाता को इन विनियमों के तहत पृथक् अनुपालन अधिकारी नामोदिष्ट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्राधिकरण ने विधिवत रूप से इस सुझाव पर विचार किया है और तदनुसार, संगत उपबंधों को विधिवत् रूप से संशोधित कर दिया गया है। इस विनियम के अनुसार टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक प्रसारक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यह अपेक्षित है कि वह विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करे। टेलीविजन चैनलों के प्रसारकों और डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस विनियम के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर वेबसाइट www.trai.gov.in पर प्राधिकरण द्वारा होस्ट किए गए सेवा प्रदाता के पोर्टल [www.spp.trai.gov.in]² पर अनुपालन अधिकारी के नाम/ ब्योरे के बारे में जानकारी देना अपेक्षित है।

अंतःसंयोजन संबंधी ब्योरे के बारे में रिपोर्टिंग करने से छूट

22. परामर्श पत्र में यह प्रस्तावित था कि प्राधिकरण अंतःसंयोजन करारों के बारे में सूचना देने से कतिपय वर्ग के सेवा प्रदाताओं को छूट दे सकता है। इस मुद्दे पर कुछ हितधारकों ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा दी गई कोई छूट पारदर्शी होनी चाहिए और यह इसको समान रूप से प्रयोज्य बनाना चाहिए। प्रारूप विनियम से संबंधित परामर्श प्रक्रिया के दौरान कई हितधारकों ने इस बात का समर्थन किया कि किसी भी एमएसओ को छूट नहीं दी जानी चाहिए।
23. प्राधिकरण ने पाया कि इस उद्योग में 1143³ सक्रिय एमएसओ और लगभग 100,000 एलएसओ कार्यरत हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1061 सक्रिय एमएसओ हैं जिनका सब्सक्राइबर आधार 1 लाख सब्सक्राइबरों से कम है। यह देखा गया है कि अनेक एमएसओ छोटे सेवा प्रदाता हैं जो दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों में कम संख्या में सब्सक्राइबरों को सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही, चूंकि भारत में मार्च, 2017 में ही केबल टीवी डिजिटलीकरण का कार्य पूरा हुआ है, इसलिए, डिजिटल एड्रैसेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म में कुछ एमएसओ का प्रचालन शैशवावस्था में हैं। ऐसे छोटे एमएसओ की श्रमशक्ति और वित्त दोनों के संदर्भ में क्षमता संबंधी व्यवधान हो सकते हैं। इसलिए, आरंभ में केवल उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटरों से सूचना मांगना उपयुक्त हो सकता है जिनके पास पर्याप्त सब्सक्राइबर आधार हो। इसके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एक लाख अथवा इससे अधिक सब्सक्राइबर आधार वाले एमएसओ के पास 85 प्रतिशत से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि केवल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिनके पास वर्ष के मार्च माह में एक लाख या इसे ज्यादा सक्रिय सब्सक्राइबर आधार हैं, वे अपने अंतःसंयोजन करारों के बारे में सूचना देनी होगी (अर्थात्, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिनके पास मार्च 2019 में 1,00,000 सब्सक्राइबरों का सक्रिय सब्सक्राइबर आधार है, तो उन्हें सभी अंतःसंयोजन करारों के संबंध में जानकारी देंगे)। तथापि, सभी डीपीओ अपने वाहक आरआईओ (अर्थात् अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के विनियम 8 के अनुसार टेलीविजन चैनल के डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रकाशित आरआईओ) के बारे में प्राधिकरण को सूचना देंगे। मार्च माह के लिए औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार की गणना अंतःसंयोजन विनियम, 2017 में यथा विहित पद्धति के अनुरूप किया जाएगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिनके पास मल्टी हेड-एंड हो, गणना के लिए उनके द्वारा प्रचालित सभी हेड-एंड सहित सभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सब्सक्राइबरों को शामिल किया जाएगा।
24. ऐसे कुछ एमएसओ हैं जो संयुक्त उद्यमों के रूप में भिन्न कंपनियों का प्रचालन कर रहे हैं। किसी एमएसओ या इसके कोई संयुक्त उद्यम सहभागी अंतःसंयोजन के पंजीकरण के लिए रिपोर्ट करने के अर्हक होते हैं, अर्थात् वे 'रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर' होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटरों के रूप में कार्य करने वाले इसके सभी संयुक्त उद्यम सहभागी/ सह-कंपनियों को अंतःसंयोजन करारों को प्रस्तुत करना चाहिए।
25. इसके अतिरिक्त, इन विनियमों में यह भी उपबंध है कि यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर कभी रिपोर्टिंग सीमा को पार करते हैं तो उन्हें 'रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर' का दर्जा प्राप्त होगा। इसके उपरान्त, यदि बाद के वर्षों में किसी रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर का सब्सक्राइबर आधार इस सीमा से नीचे गिरता है, तो वह रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, प्राधिकरण को अनुपालन अधिकारी द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसका सब्सक्राइबर आधार उस वर्ष में न्यूनतम सीमा से नीचे है।
26. यदि डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे इस उप-विनियम के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं है, उसके सम्पूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार किसी बाद के वर्ष के मार्च माह में एक लाख (एक सौ हजार) सब्सक्राइबर से ज्यादा हो जाता है तो इस उप-विनियम के अंतर्गत ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को उस वर्ष के मार्च माह से किए गए सभी अंतःसंयोजन करार की जानकारी प्रदान करना अपेक्षित है। डिस्ट्रीब्यूटर को स्पष्ट रूप से बताना अपेक्षित है कि क्या उसका औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार एक लाख से ज्यादा है अथवा कम।
27. इस प्रकार, रिपोर्टिंग सीमा से नीचे औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार वाले डिस्ट्रीब्यूटर को अंतःसंयोजन संबंधी करारों के ब्योरे की रिपोर्ट करने की बाध्यता से छूट प्राप्त है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर अपने वाहक आरआईओ के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे। यह छूट व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई है और सीमा के नीचे सब्सक्राइबर आधार और सीमित संसाधनों वाले एमएसओ पर वि. नियामक भार को कम करना है। तथापि, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों को स्वेच्छा से सूचना देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उद्योग का समग्र डॉटा रजिस्टर में उपलब्ध हो। इससे प्राधिकरण को उद्योग पर बेहतर ढंग से निगरानी रखने में सहायता मिलेगी और उद्योग का एकसमान विकास के लिए उपयुक्त उपाय/ निर्णय लिया जा सकेगा। प्राधिकरण इस विनियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का विकास कर रहा है, प्राधिकरण एक लाख से कम औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार वाले एमएसओ को भविष्य में अपने वाहक अंतःसंयोजन करारों का ब्योरे की रिपोर्ट भी करने का अधिदेश दे सकता है। प्राधिकरण एक लाख सब्सक्राइबर की रिपोर्टिंग सीमा की समय-समय पर समीक्षा करेगा।

² अथवा समय-समय पर यथा विहित

³ जनवरी 20, 2019 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार

रिपोर्टिंग की अवधि

28. प्रारंभ में, जब दिनांक 31 दिसंबर, 2004 में रजिस्टर विनियम, 2004 अधिसूचित किया गया था, तो सूचना की त्रैमासिक रिपोर्टिंग करने का प्रावधान था। लेकिन वर्ष 2009 में इस प्रावधान की समीक्षा कर वार्षिक रिपोर्टिंग कर दिया गया। परामर्श पत्र को मासिक रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया जहां सेवा प्रदाता को माह के दौरान किए गए सभी कार्यों के बारे में सूचना देने की आवश्यकता होगी और ऐसी सूचना उस माह के समाप्त होने के बाद 10 दिन के अंदर देनी होगी।
29. इस मुद्दे पर कुछ हितधारकों ने टिप्पणी की कि रिपोर्ट की अवधि वर्ष में केवल एक बार होनी चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि बेहतर हो कि सेवा प्रदाताओं के लिए इस अवधि को बदल कर वर्ष में दो बार कर दिया जाए क्योंकि टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रसारकों द्वारा बारंबार नए चैनलों को आरंभ करने, संशोधन या इसमें कुछ जोड़ने आदि से सूचना बिल्कुल ही परिवर्तनशील हो गई है। डॉटा को मासिक या त्रैमासिक आधार पर अद्यतन करना बहुत ही दुरुह और कठिन कार्य हो जाएगा। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि सेवा प्रदाताओं को अपने अंतःसंयोजन कार्यों के बारे में ब्योरा त्रैमासिक आधार पर देना चाहिए। एक हितधारक ने टिप्पणी की कि यदि तिमाही के दौरान कोई करार नहीं हुआ तो सेवा प्रदाता को शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि उस तिमाही में कोई करार नहीं हुआ है। परामर्श के दौरान कुछ हितधारक प्रारूप विनियम में किए गए प्रस्ताव के अनुसार अंतःसंयोजन संबंधी करार के बारे में मासिक रिपोर्टिंग करने पर सहमत थे। उनके अनुसार, जैसे ही अंतःसंयोजन संबंधी करार होता है, ऐसे कार्यों के बारे में सूचना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को बिना विलंब और छल-कपट प्रदान की जानी चाहिए।
30. प्राधिकरण ने नोट किया कि उद्योग में यह परिपाटी है कि वे बहुधा वार्षिक आधार पर अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करते हैं। चूंकि पूर्व विनियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग करने की अवधि वर्ष में एक बार थी, इसलिए जब कभी इन कार्यों के बारे में रिपोर्ट किया जाता था तो उनकी वैधता अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी होती थी। इसलिए, ऐसे मामलों में कोई सुधारात्मक कार्यवाई करना व्यवहार्य नहीं था, चाहे यह आवश्यक ही क्यों नहीं था। इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने पाया कि अंतःसंयोजन करार करने के बाद इससे संबंधित सूचना की रिपोर्टिंग औचित्य समय-सीमा के अंदर होनी चाहिए ताकि गैर-विभेदकारी और निगरानी के सिद्धांतों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। विनियामक द्वारा आवश्यक पर्यवेक्षण के साथ हितधारकों पर अनुपालन भार के मध्य संतुलन बनाना अपेक्षित है। तदनुसार, विभिन्न टि.पणियों, मार्केट सूचना पर विचार करने और अपने विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अंतःसंयोजन कार्यों से संबंधित सूचना की रिपोर्ट करना, ऐसे करार करने, आशोधनों, संशोधनों या परिशिष्ट, जैसा भी मामला हो, के तीस दिन के अंदर की जाए। प्राधिकरण का विचार है कि हस्ताक्षर करने की तिथि से तीस दिन के अंदर करार के ब्योरा की रिपोर्टिंग करने से प्रसारकों और डीपीओ पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा क्योंकि एक करार की सूचना केवल एक बार करना अपेक्षित है। जब करार के बारे में जानकारी प्रदान कर दी जाती है तो तब तक फिर से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाए। केवल ऐसे मामलों में ऐसे संशोधन में हस्ताक्षर किए जाने पर तीस दिन के अंदर संशोधन की रिपोर्ट करना अपेक्षित है। इस प्रकार, करार या करार में कोई संशोधन की रिपोर्ट एक बार करना अपेक्षित है। इसलिए, किसी प्रसारक या डिस्ट्रिब्यूटर पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है। वास्तव में, शतप्रतिशत कार्यों या संशोधनों को एक ही बार में बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग करने के बजाय ऐसे रिपोर्टिंग करने से संतुलन बना रहता है और पूरे वर्ष रिपोर्टिंग होती रहती है।
31. प्रसारक अथवा रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर अपने सभी अंतःसंयोजन कार्यों का ब्योरा ऐसे करार करने या आशोधन करने या संशोधन करने या परिशिष्ट, जैसा भी मामला हो, की तिथि से तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को प्रदान करेगा। प्राधिकरण का विचार है कि रिपोर्टिंग में दोहराव होने से बचने के लिए जब किसी विशेष करार के बारे में भादूविप्रा को रिपोर्ट किया जाता है तो इसी करार के बारे में तब तक रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए जब तक ऐसे करार में कोई परिवर्तन/ आशोधन नहीं किया जाता है। नया प्रसारक भी अंतःसंयोजन कार्यों की सूचना ऐसे करार करने या आशोधन करने या संशोधन करने या परिशिष्ट, जैसा भी मामला हो, की तिथि से तीस दिन के अंदर करेगा।
32. टेलीविजन चैनलों के रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर अपने और प्रसारक के मध्य हस्ताक्षरित सभी विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में प्रसारक द्वारा दायर सूचना को पंद्रह दिनों के अंदर सत्यापन करेगा। इसी प्रकार, संबंधित प्रसारक अपने और रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर के मध्य हस्ताक्षरित सभी विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में जानकारी प्रदान करने वाले रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर द्वारा दायर सूचना का पंद्रह दिनों के अंदर सत्यापन करेगा। ऐसे सत्यापन में शीघ्रता लाने के लिए प्राधिकरण संबंधित अनुपालन अधिकारी को सिस्टम समर्थित ई-मेल सृजित करने के लिए प्रयास करेगा।
33. यदि कोई प्रसारक/रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर किसी करार के संबंध में सूचना जमा करने में असफल रहता है, तो संबंधित रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर/प्रसारक सभी अंतःसंयोजन कार्यों से संबंधित सूचना ऐसे करार करने या आशोधन करने या संशोधन करने या आशोधन, जैसा भी मामला हो, की तिथि से पैंतालीस दिन के अंदर प्राधिकरण को सूचना देगा या रिपोर्ट करेगा।

रिपोर्टिंग की पद्धति और प्रारूप

34. जहां तक रिपोर्टिंग की पद्धति का संबंध है, सभी हितधारक परामर्श पत्र में यथा प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से सहमत हैं। प्राधिकरण ने नोट किया कि अंतःसंयोजन कार्यों से संबंधित सूचना का स्वरूप व्यापक होने के नाते यह प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर के हित में है कि ऐसी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट की जाए। यह प्राधिकरण और हितधारकों द्वारा दी गई ऐसी सूचना को पुनः प्राप्त करने और उसके प्रबंधन में सुलभता होगी। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में सूचना को रिपोर्ट करने के कई विकल्प हो सकते हैं, जैसे सीडी-रोम, ईमेल के माध्यम से ई-फॉइलिंग या अंतःसंयोजन कार्यों से संबंधित डॉक्यूमेंट या सूचना को वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड करना।
35. परामर्श के दौरान प्रारूप विनियम में यथा प्रस्तावित रिपोर्टिंग के प्रारूप पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गईं। प्रारूप के अतिरिक्त, वास्तविक कार्यों की प्रतियां को फाइल करने की अपेक्षा भी प्रस्तावित था। हितधारकों ने इन प्रारूपों पर भिन्न विचार व्यक्त किए। साथ ही, प्रारूपों/तालिकाओं में उल्लेखित मानदंड पूर्ववती अंतःसंयोजन विनियामक ढांचे के अनुसार थे जिसे नए ढांचे से प्रतिस्थापित किया गया है, इसलिए हितधारकों के कुछ सुझाव वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। कार्यों की प्रतियां फाइल करने के मुद्दे पर कुछ हितधारकों ने कार्यों की प्रतियां फाइल करने की अपेक्षा को हटाने का सुझाव दिया, जबकि कुछ अन्य हितधारकों ने सेवा प्रदाताओं को अपने कार्यों की

वास्तविक प्रतियां फाइल करने का अधिदेश देने पर बल दिया ताकि उनके द्वारा दी गई तालिकाबद्ध ब्योरों की प्रतियों की जांच की जा सके। अधिकांश एमएसओ ने सुझाव दिया कि एलसीओ के साथ हस्ताक्षरित अंतःसंयोजन करारों की प्रतियां फाइल करने से उन्हें छूट प्रदान की जा सकती है क्योंकि ऐसे करारों को पहले ही भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा मॉडल अंतःसंयोजन करार (एमआईए) अथवा मानक अंतःसंयोजन करार (एसआईए) में पूर्व परिभाषित किया गया है।

36. प्राधिकरण ने नोट किया कि कालक्रम में अंतःसंयोजन ढांचा में परिवर्तन और अन्य प्रासंगिक अपेक्षाओं के कारण रिपोर्ट के प्रारूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। प्राधिकरण ने व्यापक शीर्षक/मानक निर्धारित किए हैं जिसके तहत इस विनियम के कार्यक्रमों में प्रसारक अथवा टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर इस विनियम की अनुसूची में जानकारी प्रदान करेंगे। प्राधिकरण समय-समय पर उपयुक्त निदेश के माध्यम से प्रचलित विनियामक ढांचे के तर्ज पर विशिष्ट प्रारूप निर्धारित कर सकता है। यह पद्धति विनियम में संशोधनों की जरूरत को रोक सकती है। इससे प्राधिकरण, यथा- आवश्यकतानुसार अति उपयुक्त सूचना/डॉटा समुच्चय प्राप्त में सक्षम होगा।
37. टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर के साथ हस्ताक्षरित किसी करार के बारे में प्रसारक को विनियम 3(3) में उल्लिखित रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर सहित, के अनुसार सूचना का ब्योरा का रिपोर्ट देना अपेक्षित होता है। प्रसारक द्वारा प्रकाशित 'रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश' सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। इस प्रकार आरआईओ के अनुसार हस्ताक्षरित सभी अंतःसंयोजन करार का स्वरूप गोपनीय नहीं होता है। इसी तरह, प्रसारक के साथ हस्ताक्षरित किसी करार के बारे में टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर, जिनके पास औसत एक लाख के बराबर या इससे ज्यादा सक्रिय सब्सक्राइबर हैं, को विनियम 3(4) में उल्लेखित 'रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश' के अनुसार सूचना का ब्योरा का रिपोर्ट देना अपेक्षित होता है। डिस्ट्रिब्यूटर द्वारा प्रकाशित 'रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश' भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। इस प्रकार आरआईओ के अनुसार हस्ताक्षरित सभी अंतःसंयोजन करार की प्रकृति गोपनीय नहीं होती है। विनियम यह अधिदेश करता है कि प्रसारक टेलीविजन चैनल के डिस्ट्रिब्यूटर के साथ हस्ताक्षरित सभी अन्य करार जैसे प्लेसमेंट, विपणन अथवा किसी अन्य तकनीकी अथवा वाणिज्यिक व्यवस्था से संबंधित सूचना की जानकारी तीन भागों अर्थात् भाग-ए, भाग-बी और भाग-सी में देगा। भाग-ए में प्रत्येक करार/आशोधन/संशोधन या परिशिष्ट से संबंधित कतिपय मूलभूत ब्योरा यथा संविदा पार्टियों के नाम और पता, करार हस्ताक्षर करने की तारीख, करार की वैधता अवधि आदि जानकारी होगी। भाग-बी में यथा निर्धारित तालिका प्रारूप में वाणिज्यिक ब्योरा होगा। भाग-सी में ऐसे करार/आशोधन/संशोधन अथवा अनुशेष की वास्तविक प्रति इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होगी। इस विनियम के अंतर्गत प्राधिकरण सूचना फॉइल करने के लिए प्रारूप या ई-फार्म निर्धारित कर सकता है। प्राधिकरण भाग-सी में करार की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या स्कैन प्रति अथवा आरआईओ को प्रस्तुत किया जा सकता है। आरआईओ आधारित करारों के संबंध में, यह नोट किया जा सकता है कि चूंकि वे गैर-गोपनीय स्वरूप के होते हैं, जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है इसलिए समग्र जानकारी को केवल भाग-ए में ही समाहित किया जाएगा। उपयुक्त निदेश(शों) के माध्यम से प्राधिकरण अलग से ई-रिपोर्टिंग और अंतःसंयोजन करारों का ब्योरा फाइल करने संबंधी प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा।
38. प्राधिकरण ने हितधारकों के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि डिस्ट्रिब्यूटरों को एलसीओ के साथ हस्ताक्षरित करारों की प्रतियां फाइल करने हेतु अधिदेशित नहीं दिया जाना चाहिए। डिस्ट्रिब्यूटर-एलसीओ करार मानकीकृत होते हैं क्योंकि विनियम, एमआईए/एसआईए पर ऐसे करारों के हस्ताक्षर हेतु निर्धारित करता है। एलसीओ के साथ हस्ताक्षरित वास्तविक करारों की प्रतियां फाइल करने से डिस्ट्रिब्यूटर को छूट दी गई है। एमएसओ को एलसीओ के साथ हस्ताक्षरित सभी पृथक करारों का ब्योरे की जानकारी प्रदान करना अपेक्षित होता है जैसे कि संविदागत पक्षकारों के नाम और पते, करार पर किए गए हस्ताक्षर की तिथि, करार की वैधता अवधि, और करार के तहत एरिया; प्रत्येक करार के संबंध में इस बात की ओर इशारा की क्या करार पर मानक अंतःसंयोजन करार के आधार पर अथवा मॉडल अंतःसंयोजन करार के आधार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; सेवा प्रभागों का निपटान (मॉडल अंतःसंयोजन की स्थिति में), राजस्व बटवारा सहमति का ब्योरा (छूट यदि कोई हो), और प्राधिकरण द्वारा निदेश के माध्यम से समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य ब्योरे के बारे में रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है।
39. कतिपय जानकारीयां जिन्हें फॉइल करना अपेक्षित होता है, को प्राधिकरण द्वारा निदेश के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में तालिकाबद्ध ब्योरा में दिया जा सकता है और अंतःसंयोजन करार की प्रति लिखित करार की स्कैन प्रति असंपादनीय पीडीएफ प्रारूप में हो सकती है अथवा किसी अन्य प्रारूप में जिसे प्राधिकरण समय-समय पर निदेश(शों) के माध्यम से विहित करे। प्रसारक और डिस्ट्रिब्यूटर के मध्य किए गए वास्तविक करारों की प्रतियों को फाइल करना आवश्यक है। इससे प्राधिकरण को अंतःसंयोजन करार के निबंधन और शर्तों और प्रसारक तथा टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर के मध्य अन्य मामले सहित एक व्यापक और पूर्ण डॉटा का रखरखाव करने में सहायता प्राप्त होगी।

रिपोर्टों की परिशुद्धता और प्रमाणिकता

40. परिशुद्धता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए परामर्श पत्र में दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना अनिवार्य बनाने की परिकल्पना की गई है।
41. जैसा की पहले उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण विनियम के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का विकास कर रहा है। इस पोर्टल में प्रयोक्ता (अर्थात् प्रसारक, डीपीओ आदि) के प्रमाणीकरण के लिए प्रयास किया गया है और प्रत्येक प्रयोक्ता के पास रिपोर्ट करने के लिए एक पासवर्ड होगा। इस प्रकार केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही प्राधिकरण को फाइलिंग प्रस्तुत कर सकता है। अतः, प्राधिकरण का विचार है कि केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों की अनिवार्य रूप से फाइलिंग करने को अभी लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, भाग-सी, जिसमें करार की प्रति जमा करना अपेक्षित है, वह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज या स्कैन दस्तावेज (वास्तविक हस्ताक्षरित दस्तावेज की स्कैन प्रति आदि) हो सकता है।
42. निदेश(शों) के माध्यम से विनियम प्रारूप का निर्धारण और सूचना की रिपोर्टिंग की पद्धति सुनिश्चित करता है। प्रासंगिक दस्तावेज(जों) में डिजिटल हस्ताक्षरों के संबंध में उपयुक्त खंड भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि दी गई सूचना सभी संदर्भों में पूर्ण और सही है की नहीं, प्राधिकरण ने अधिदेश दिया है कि संबंधित हितधारक (अन्य पक्षकार) उनके मध्य हस्ताक्षरित सभी करारों के संबंध में प्रसारक/जानकारी प्रदान करने वाला रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर (प्रथम पक्ष) द्वारा दायर सूचना का जानकारी प्रदान करने वाला रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर/प्रसारक द्वारा फाइलिंग की तिथि से पंद्रह दिन के अंदर सत्यापन करेगा।

रिपोर्टिंग करने में विलंब के लिए वित्तीय निरुत्साहन

43. अनेक बार यह देखा गया है कि प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर नियत समय-सीमा के अंदर अपेक्षित सूचना जमा नहीं करते हैं। हितधारक इस बात की सराहना करते हैं कि समयबद्ध अनुपालन किसी विनियामक व्यवस्था का मूल तत्व है। कई हितधारकों ने पाया कि प्रचलित व्यवस्था में वे उपयुक्त खंड नहीं हैं जो विलंब से फाइलिंग करने से हतोत्साहित करें। टिप्पणियों और चर्चाओं के आधार पर यह बात उभरती है कि विलंब से जमा करने पर कुछ निरुत्साहन लगाना, समयबद्ध अनुपालन में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकरण ने प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर को रिपोर्टिंग करने में विलंब करने पर वित्तीय निरुत्साहन उदग्रहण करने को विहित किया है। 'ग्रेडेड मानों' पर वित्तीय निरुत्साहन उदग्रहण का प्रस्ताव है। अर्थात्, यदि देय तिथि तक सूचना नहीं दी जाती है तो प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर पहले तीस दिन विलंब करने के लिए प्रतिदिन एक हजार रुपए का भुगतान करेगा। यदि तीस दिन से भी अधिक का विलम्ब होता है तो वित्तीय निरुत्साहन की राशि में वृद्धि हो जाएगी और पहले तीस दिनों के बाद 2000 रुपये प्रति अतिरिक्त दिन होगा। इसलिए, यदि प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर देय तिथि के 40 दिन बाद सूचना देता है तो वित्तीय निरुत्साहन की गणना निम्नानुसार होगी :

क. उदाहरण : 40 दिन के विलंब के लिए वित्तीय निरुत्साहन की गणना :

पहले 30 दिनों के लिए वित्तीय निरुत्साहन = रु. 30000/- (@1000 X 30)

अगले 10 दिनों के लिए वित्तीय निरुत्साहन = रु. 20000/- (@2000 X (40-30))

कुल वित्तीय निरुत्साहन = 50000/- रुपए

44. इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण का मत है कि अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन की अधिकतम सीमा होनी चाहिए। इसलिए, प्राधिकरण ने अधिकतम दो लाख रुपये की सीमा निर्धारित की है। विनियम में यथा निर्धारित अधिकतम सीमा प्रत्येक अपेक्षित प्रस्तुति और प्रत्येक देय तिथि के लिए प्रयोज्य है। यह पुनः दोहराया जाता है कि प्रत्येक आरआईओ/करार या अन्य मामले, जैसा प्रयोज्य हो, के संबंध में वित्तीय निरुत्साहन की गणना अनिवार्य फाइलिंग के लिए अलग से की जाएगी।
45. यदि प्रसारक और टेलीविजन चैनलों के रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर दोनों किसी करार के बारे में रिपोर्ट करने में असफल रहते हैं तो वित्तीय निरुत्साहन के अतिरिक्त ऐसे प्रसारक और रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर, दोनों पर प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के प्र. 17(1) के अनुसार ऐसे दोषी सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार, कोई सूचना देने पर असफल रहने के लिए प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर पर प्राधिकरण द्वारा कोई वित्तीय निरुत्साहन का उदग्रहण, किसी भी तरह से प्रसारक या टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रिब्यूटर का ऐसे सूचना के रिपोर्टिंग के दायित्व निर्वहन में कमी नहीं माना जाना चाहिए। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण को वित्तीय निरुत्साहन के उदग्रहण के अतिरिक्त दोषी प्रसारक या टेलीविजन चैनल के डिस्ट्रिब्यूटर और इसके अनुपालन अधिकारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के अधिकार हैं।

रजिस्टर का अनुरक्षण और सूचना की उपलब्धता

46. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकरण ने हितधारकों से स्पष्ट रूप से यह पूछा कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सभी वाणिज्यिक सूचना इच्छित हितधारकों के लिए उपलब्ध क्यों नहीं कराई जानी चाहिए। इस मुद्दे पर हितधारकों से विभिन्न मत प्राप्त हुए हैं।
47. कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि चूंकि वाणिज्यिक संविदाओं के संदर्भ में संवेदनशील वाणिज्यिक सूचना की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य सुरक्षोपाय है, इसलिए इसे किसी तीसरे पक्ष को नहीं उद्घटित किया जाना चाहिए। कुछ प्रसारकों ने टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के अंतर्गत प्रत्याभूत वृत्ति और व्यापार करने का अधिकार के तहत वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना का संरक्षण उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भादूविप्रा को कतिपय सूचना को गोपनीय या अगोपनीय रखने के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 के विनियम 35 के अंतर्गत दिए गए प्रक्रियाओं के समान ही प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं द्वारा दायर सभी अंतःसंयोजन करारों की स्वयं जांच करनी चाहिए और तत्पश्चात् प्राधिकरण को उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि केवल सूचना के रूझान का विश्लेषण ही आम जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
48. दूसरी ओर, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि केवल ऐसे इच्छित सेवा प्रदाताओं को सूचना उपलब्ध होनी चाहिए जिनके पास वैध लाइसेंस हों। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि सही अर्थों में गैर-विभेदकारी का भाव तभी प्राप्त हो सकता है जब प्रत्येक प्रकार की सूचना उपलब्ध हो ताकि कोई भी गैर-विभेदकारी आधार पर चैनल प्राप्त कर सके। उनके मत है कि प्रासंगिक वाणिज्यिक सूचना तक पहुंच प्रदान करने से सेवा प्रदाताओं को डौटा और रूझान देखकर अंतःसंयोजन करार करने में सहायता मिलेगी और यह समान अवसर उपलब्ध कराएगा तथा दक्षता आधारित प्रतिस्पर्धा एवं सेवा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करेगा और इसे प्रभावी रूप से पारदर्शिता और गैर-विभेदकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।
49. प्राधिकरण का मत है कि 'रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश' के अनुसार प्रसारक/डिस्ट्रिब्यूटर को डिस्ट्रिब्यूटर/प्रसारक के साथ हस्ताक्षरित करारों की सूचना का ब्योरे जिसे रिपोर्ट करना अपेक्षित है, गैर गोपनीय स्वरूप का है चूंकि प्रसारक/डिस्ट्रिब्यूटर द्वारा प्रकाशित 'रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश' सावर्जनिक रूप से उपलब्ध होता है। इस प्रकार आरआईओ के अनुसार हस्ताक्षरित सभी अंतःसंयोजन करार का स्वरूप गोपनीय नहीं होते हैं।
50. कुछ हितधारकों ने डिजिटल दस्तावेजों/स्कैन करारों के माध्यम से संवेदनशील सूचना की गोपनीयता की सुरक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। प्राधिकरण ऐसे सूचना की संपूर्ण डौटा सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। प्रसारकों और डिस्ट्रिब्यूटरों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों/करारों को कूटबद्ध प्रारूप में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, डिजिटल दस्तावेजों/स्कैन दस्तावेजों को सामान्यतः ऑफलाइन

पद्धति से रखा जाएगा। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगा कि रजिस्टर में उल्लेखित डॉटा तब तक सुलभ नहीं हों जब तक रजिस्टर की जांच के वर्तमान उपबंधों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट न हों।

51. प्राधिकरण ने दो भागों में अंतःसंयोजन करारों के रजिस्टर का रखरखाव करने का निर्णय लिया है अर्थात् भाग-I और भाग-II, भाग-I में (ए) विनियम 3 के उप विनियम (1), (2), (4) और (5) के तहत प्रदान की गई जानकारी; और (बी) विनियम 3 के उप विनियम (3) के तहत भाग 'ए' में यथा संसूचित की गई जानकारी; और भाग-II में विनियम 3 के उप विनियम (3) के तहत भाग 'बी' और भाग 'सी' में यथा संसूचित जानकारी अंतर्विष्ट होगी। रजिस्टर को गैर गोपनीय माना जाएगा, जब तक कि अंतःसंयोजन करार में पक्षकार कोई पक्ष प्राधिकरण को वि. नियमों में विहित पद्धति तथा प्ररूप में भाग-II में संसूचित करार के किसी भाग को गोपनीय मानने के संबंध में अनुरोध नहीं करता है। गोपनीयता बरतने के अनुरोध को लिखित में तथा गोपनीय रखे जाने वाले भाग की गैर-गोपनीयता संबंधी सारांश के साथ भेजा जाएगा। सेवा प्रदाता यह स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे कि किस पैरा तथा तत्संबंधी भाग को गोपनीय माना जाए। ऐसे अनुरोध के साथ-साथ ऐसी जानकारी को गोपनीय मानने के कारण(णों) का ब्योरा भी संलग्न किया जाएगा। यदि प्राधिकरण का गोपनीयता के अनुरोध को अस्वीकार करने का प्रस्ताव हो तो वह, सेवा प्रदाता को लिखित में ऐसा किए जाने के कारणों का उल्लेख करेगा तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इस निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दायर करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। ऐसे अभ्यावेदन, यदि कोई हों तो, पर विचार करने पर, प्राधिकरण अंतिम निर्णय लेगा। यदि प्राधिकरण सेवा प्रदाता के अनुरोध को अस्वीकार करता है तो वह ऐसा किए जाने के कारणों सहित इसे लिखित में सम्प्रेषित करेगा। इस प्रकार, विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधधीन, विनियम के तहत विहित शुल्क के भुगतान पर जन साधारण से किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

अनुसूची-I

[उल्लेखे विनियम 3 का उप विनियम (1)]

प्रसारकों द्वारा रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर की जानकारी

तालिका (Iए) (सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)		
क्रम संख्या	मानदंड	उपलब्ध कराया जाने वाला ब्योरा
1	सेवा प्रदाता का नाम	
2	आरआईओ का ब्योरा	संख्या : दिनांक : आरआईओ की सॉफ्ट कापी को 'वर्ड' तथा 'पीडीएफ' प्ररूप में संलग्न करें (दोनों संस्करणों को प्रस्तुत किया जाए)

तालिका (Iबी) चैनलों की सूची (सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

क्रम संख्या	चैनल का नाम	चैनल का स्वरूप (पे/एफटीए)	चैनल का जेनरे	पे चैनल*		
				अधिकतम खुदरा मूल्य प्रतिमाह	डीपीओ को अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट, यदि कोई प्रदान की गई हो।	संवितरण शुल्क*

*अंतःसंयोजन विनियम 2017 के विनियम 7 के अनुसार जानकारी

तालिका (Iसी) बुके की सूची (सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

(बुके की कुल संख्या....)						
क्रम संख्या	बुके का नाम	बुके में चैनलों की संख्या	बुके में चैनलों के घटक का नाम	पे चैनलों के बुके का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रतिमाह	वितरकों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर कोई छूट, यदि प्रदान की गई हो,	संवितरण शुल्क*

*अंतःसंयोजन विनियम 2017 के विनियम 7 के अनुसार जानकारी

अनुसूची-II

{देखें विनियम 3 का उप विनियम (2)}

सभी वितरकों द्वारा रेफरेंस अंतःसंयोजन पेशकश की जानकारी

तालिका (IIए)		
क्रम संख्या I	मानदंड	उपलब्ध कराए जाने वाला ब्योरा
1	सेवा प्रदाता का नाम	
2	डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म का स्वरूप (एमएसओ/एचआईटीएस/आईपीटीवी / डीटीएच)	
3	आरआईओ का ब्योरा	संख्या : दिनांक : आरआईओ की सॉफ्ट कापी को 'वर्ड' तथा 'पीडीएफ' प्ररूप में संलग्न करें (दोनों संस्करणों को प्रस्तुत किया जाए)
4	चैनल वहन करने की क्षमता, प्लेटफार्म पर वर्तमान में धारित चैनलों की वास्तविक संख्या तथा अतिरिक्त चैनलों की क्षमता	चैनल वहन करने की क्षमता वर्तमान में धारित चैनलों की वास्तविक संख्या अतिरिक्त चैनलों की क्षमता
5	औसत सक्रिय सब्सक्राइबर आधार (देखें विनियम 8 का उप विनियम 2 और अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के अनुसूची VII)	एसडी एचडी कुल लंबित अनुरोधों की संख्या*
6	कैरिज शुल्क	कैरिज शुल्क छूट (यदि कोई हो तो)
7	क्या आप 'रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर' हैं**	हाँ/ नहीं

* अंतःसंयोजन विनियम के विनियम 4 के उप विनियम (4) (एफ) को देखें। कृपया लंबित चैनलों की सूची संलग्न करें।

** ब्योरे के लिए विनियम 2(के के) में यथा उपबंधित रिपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर की परिभाषा का संदर्भ ग्रहण करें।

तालिका (IIबी) चैनलों की सूची*					
क्रम संख्या	चैनल का नाम	चैनल का स्वरूप (पे/ एफटीए)	पे चैनल की डीआरपी	जेनरे	ईपीजी पर चैनल नम्बर

* अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के विनियम 8 और विनियम 4 के अनुसार जानकारी।

तालिका (IIसी) बुके की सूची* (सभी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)			
क्रम संख्या	बुके का नाम	बुके में संघटक चैनलों का नाम	बुके की डीआरपी

* अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के विनियम 8 और विनियम 4 के अनुसार जानकारी।

तालिका (IIडी) टारगेट मार्केट * (सभी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)			
क्रम संख्या	हैड एंड लोकेशन	टारगेट मार्केट का ब्योरा	टिप्पणियां, यदि कोई हों तो

* अंतःसंयोजन विनियम, 2017 के विनियम 8 और विनियम 4 के अनुसार जानकारी।

अनुसूची— III

{देखें विनियम 3 का उप विनियम (3)}

टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हस्ताक्षरित व्यक्तिगत करार का ब्योरा

(सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

तालिका (IIIए): भाग-ए (आरआईओ आधारित करार से संबंधित, जिसकी जानकारी सभी पे चैनल(लों) वाले प्रसारकों द्वारा दी जानी है												
क्रम संख्या	करार संख्या	डीपीओ का नाम	डीपीओ का पता	करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि	वैधता अवधि		कवर किया गया एरिया	अलाकार्ट पे चैनलों की संख्या	अलाकार्ट पे चैनलों का नाम	पे चैनलों के बुके का नाम	सहमत हुआ संवितरण शुल्क	अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट की राशि (प्रतिशत में)
					से	तक						

प्लेसमेंट, विपणन अथवा किसी अन्य तकनीकी अथवा वाणिज्यिक करार हेतु करार (सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

	तालिका (IIIबी): भाग-ए							
क्रम संख्या	करार संख्या	करार का टाइप/नाम/ स्वरूप (प्लेसमेंट, विपणन अथवा किसी अन्य तकनीकी अथवा वाणिज्यिक करार)	डीपीओ का नाम	डीपीओ का पता	करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि	वैधता अवधि		कवर किया गया एरिया
						से	तक	

प्लेसमेंट, विपणन अथवा किसी अन्य तकनीकी अथवा वाणिज्यिक करार हेतु करार (सभी प्रसारकों द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

तालिका (IIIसी)											
	भाग-ए							भाग-बी		भाग-सी	
क्रम संख्या	करार संख्या	करार का टाइप/ नाम/ स्वरूप (प्लेसमेंट, विपणन अथवा किसी अन्य तकनीकी अथवा वाणिज्यिक करार)	डीपीओ का नाम	डीपीओ का पता	करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि	वैधता अवधि		कवर किया गया एरिया	मौद्रिक हेतु- राशि रुपए में	गैर- मौद्रिक प्रोत्साहन का ब्योरा	करार की स्कैन/ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रति
						से	तक				
नोट: भाग बी एवं भाग सी को, विनियम 6 का उप विनियम (1) से (3) के तदनुसार, गोपनीय माना जायेगा											

नोट: भाग बी एवं भाग सी को, विनियम 6 का उप विनियम (1) से (3) के तदनुसार, गोपनीय माना जायेगा

अनुसूची- IV

{देखें विनियम 3 का उप विनियम (4)}

(सभी डिस्ट्रिब्यूटर्स द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

प्रसारकों के साथ हस्ताक्षरित सभी पृथक करारों का ब्योरा जिनके संबंध में टेलीविजन चैनलों के पुनर्प्रसारण हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है														
क्रम संख्या	करार संख्या	प्रसारक का नाम	प्रसारक का पता	करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि	वैधता अवधि		करार द्वारा कवर किया गया एरिया	अलाकार्ट पे चैनल और/अथवा एफटीए चैनल की संख्या	करार द्वारा कवर किया जाने वाले चैनलों का नाम	करार द्वारा कवर किया जाने वाले चैनलों का स्वरूप (पे अथवा एफटीए)	पे चैनल और/अथवा एफटीए चैनलों के बुके का नाम	पे और/अथवा एफटीए चैनलों के प्रत्येक बुके के संघटक पे चैनल और/अथवा एफटीए चैनलों का नाम	करार द्वारा कवर किए गए प्रत्येक चैनल के संबंध में सहमत हुआ कैरिज शुल्क (रुपए में)	चैनल के संबंध में सहमत हुए छूट के प्रतिशत की प्रमात्रा (कैरिज शुल्क का प्रतिशत)
					से	तक								

अनुसूची- V

{देखें विनियम 3 का उप विनियम (5)}

(सभी रिपोर्टिंग डिस्ट्रिब्यूटर्स द्वारा जानकारी प्रदान की जाए)

स्थानीय केबल आपरेटर के साथ करार का ब्योरा													
क्रम संख्या	करार संख्या	एलसीओ का नाम	एलसीओ का पता	करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि	वैधता अवधि		करार द्वारा कवर किया गया एरिया	विनिर्दिष्ट करें कि किस आधार पर करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं (एमआईए/एसआईए)	सेवा प्रभारों (1) का निपटान		छूट	सहमत हुआ कोई अन्य शुल्क (2)	टिप्पणियां (3)
					से	तक			संवितरण शुल्क में एलसीओ की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	नेटवर्क क्षमता शुल्क में एलसीओ की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)			

1) इस कॉलम को केवल तभी भरें जब एमआईए पर हस्ताक्षर कर दिए गए हों और एमएसओ और एलसीओ के बीच सेवा प्रभार को संवितरण शुल्क और नेटवर्क क्षमता शुल्क के अनुरूप संवितरित किया जाना हो।

2) इस कॉलम को केवल एमआईए की स्थिति में ही भरें जब एमएसओ और एलसीओ के बीच संवितरण शुल्क और नेटवर्क क्षमता शुल्क के संवितरण के अलावा, सेवा प्रभार के निपटान हेतु पृथक व्यवस्था हो।

3) व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करें यदि एमएसओ और एलसीओ के बीच संवितरण शुल्क और नेटवर्क क्षमता शुल्क के संवितरण से भिन्न, व्यवस्था हो।

अनुसूची- VI

{देखें विनियम 7 का उप विनियम (3)}

अनुपालन अधिकारी से संबंधित जानकारी

क्रम संख्या	मानदंड	ब्योरा
1	सेवा प्रदाता का नाम	
2	सेवा प्रदाता का स्वरूप (प्रसारक / एमएसओ / एचआईटीएस / आईपीटीवी / डीटीएस)	
3	सेवा प्रदाता का पंजीकृत पता	
4	प्राधिकृत करने वाले अधिकारी / व्यक्ति का नाम	
5	प्राधिकृत करने वाले अधिकारी / व्यक्ति का पदनाम	
6	प्राधिकृत करने वाले अधिकारी / व्यक्ति का संपर्क ब्योरा	दूरभाष (कार्यालय) : (मोबाइल) : ई- मेल
7	बोर्ड के संकल्प / प्राधिकार पत्र का ब्योरा	संख्या दिनांक : (अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रति संलग्न की जाए)
8	क्या मूल / परिवर्तित नामांकन	मूल / परिवर्तित
9	अनुपालन अधिकारी का नाम	
10	अनुपालन अधिकारी का संपर्क ब्योरा	दूरभाष (कार्यालय) : (मोबाइल) : ई- मेल

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 2019

F. No. 6-1/2016- B&CS.— In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (vii) and (viii) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 and section 12 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (No. 24 of 1997), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39, —

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and

(b) published under notification No. S.O. 44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, —

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely: -

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES**REGISTER OF INTERCONNECTION AGREEMENTS AND ALL SUCH OTHER MATTERS
REGULATIONS, 2019**

(No. 02 of 2019)

CHAPTER- I**PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement. -- (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Register of Interconnection Agreements and all such other matters Regulations, 2019.

(2) These regulations shall be applicable to all commercial and technical arrangements entered into by broadcaster, distributor of television channels and local cable operator for providing broadcasting services relating to television provided through addressable systems throughout the territory of India.

(3) (a) Except as otherwise provided in sub-clause (b), these regulations shall come into force after one hundred and twenty days from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.

(b) Regulation 7 shall come into force from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:-

- (a) “Act” means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (No. 24 of 1997);
- (b) “active subscriber” means a subscriber who has been authorized to receive signals of television channels as per the subscriber management system and whose set top box has not been denied signals;
- (c) “addressable system” means an electronic device (which includes hardware and its associated software) or more than one electronic device put in an integrated system through which transmission of programmes including re-transmission of signals of television channels can be done in encrypted form, which can be decoded by the device or devices at the premises of the subscriber within the limits of the authorization made, on the choice and request of such subscriber, by the distributor of television channels;
- (d) “a-la-carte” or “a-la-carte channel” with reference to offering of a television channel means offering the channel individually on a standalone basis;
- (e) “Authority” means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (No. 24 of 1997);
- (f) “average active subscriber base” means the number arrived at by averaging the active subscriber base count in the manner specified in the Schedule VII of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017;

- (g) “bouquet” or “bouquet of channels” means an assortment of distinct channels offered together as a group or as a bundle and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
- (h) “broadcaster” means a person or a group of persons, or body corporate, or any organization or body who, after having obtained, in its name, downlinking permission for its channels, from the Central Government, is providing programming services;
- (i) “broadcaster’s share of maximum retail price” with reference to a pay channel or a bouquet of pay channels means any fee payable by a distributor of television channels to a broadcaster for signals of pay channel or bouquet of pay channels, as the case may be, and for which due authorization has been obtained by such distributor from that broadcaster;
- (j) “broadcasting services” means the dissemination of any form of communication like signs, signals, writing, pictures, images and sounds of all kinds by transmission of electro-magnetic waves through space or through cables intended to be received by the general public either directly or indirectly and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;
- (k) “cable service” or “cable TV service” means the transmission of programmes including re-transmission of signals of television channels through cables;
- (l) “cable television network” or “cable TV network” means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signal generation, control and distribution equipment, designed to provide cable service for reception by multiple subscribers;
- (m) “carriage fee” means any fee payable by a broadcaster to a distributor of television channels only for the purpose of carrying its channels through the distributor’s network, without, specifying the placement of such channels onto a specific position in the electronic programme guide or, seeking assignment of a particular number to such channels;
- (n) “compliance officer” means any person designated so, who is capable of appreciating requirements for regulatory compliance under these regulations, by a service provider;
- (o) “direct to home operator” or “DTH operator” means any person who has been granted license by the Central Government to provide direct to home (DTH) service;
- (p) “direct to home service” or “DTH service” means re-transmission of signals of television channels, by using a satellite system, directly to subscriber’s premises without passing through an intermediary such as local cable operator or any other distributor of television channels;
- (q) “distribution fee” means any fee payable by a broadcaster to a distributor of television channels for the purpose of distribution of pay channel or bouquet of pay channels, as the case may be, to subscribers and it does not include carriage fee;
- (r) “distribution platform” means distribution network of a DTH operator, multi- system operator, HITS operator or IPTV operator;
- (s) “distributor of television channels” or “distributor” means any DTH operator, multi-system operator, HITS operator or IPTV operator;
- (t) “electronic programme guide” or “EPG” means a program guide maintained by the distributors of television channels that lists television channels and programmes, and scheduling and programming information therein and includes any enhanced guide that allows subscribers to navigate and select such available channels and programmes;
- (u) “free-to-air channel” or “free-to-air television channel” means a channel which is declared as such by the broadcaster and for which no fee is to be paid by the distributor of television channels to the broadcaster for signals of such channel;
- (v) “head end in the sky operator” or “HITS operator” means any person permitted by the Central Government to provide head end in the sky (HITS) service;
- (w) “head end in the sky service” or “HITS service” means transmission of programmes including re-transmission of signals of television channels—

- (i) to intermediaries like local cable operators or multi-system operators by using a satellite system and not directly to subscribers; and
 - (ii) to the subscribers by using satellite system and its own cable networks;
- (x) “interconnection” means commercial and technical arrangements under which service providers connect their equipment and networks to provide broadcasting services to the subscribers;
- (y) “interconnection agreement” with all its grammatical variations and cognate expressions means agreements on interconnection providing technical and commercial terms and conditions for distribution of signals of television channel;
- (z) “Interconnection Regulations” means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 dated 3rd March 2017;
- (aa) “internet protocol television operator” or “IPTV operator” means a person permitted by the Central Government to provide IPTV service;
- (bb) “internet protocol television service” or “IPTV service” means delivery of multi-channel television programmes in addressable mode by using Internet Protocol over a closed network of one or more service providers;
- (cc) “local cable operator” or “LCO” means a person registered under rule 5 of the Cable Television Networks Rules, 1994;
- (dd) “maximum retail price” or “MRP” for the purpose of these regulations, means the maximum price, excluding taxes, payable by a subscriber for a-la-carte pay channel or bouquet of pay channels, as the case may be;
- (ee) “multi-system operator” or “MSO” means a cable operator who has been granted registration under rule 11 of the Cable Television Networks Rules, 1994 and who receives a programming service from a broadcaster and re-transmits the same or transmits his own programming service for simultaneous reception either by multiple subscribers directly or through one or more local cable operators;
- (ff) “pay broadcaster” means a broadcaster which has declared its one or more channels as pay channel to the Authority under the provisions of applicable regulations or tariff order, as the case may be;
- (gg) “pay channel” means a channel which is declared as such by the broadcaster and for which a share of maximum retail price is to be paid to the broadcaster by the distributor of television channels and for which due authorization needs to be obtained from the broadcaster for distribution of such channel to subscribers;
- (hh) “programme” means any television broadcast and includes-
 - (i) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials;
 - (ii) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation;and the expression “programming service” shall be construed accordingly
- (ii) “reference interconnection offer” or “RIO” is a document published by a service provider specifying terms and conditions on which the other service provider may seek interconnection with such service provider;
- (jj) “register” means the register of interconnection agreements and all such other matters, maintained by the Authority in the form as it may decide from time to time;
- (kk) “reporting distributor” means a distributor whose average active subscriber base of its entire distribution network, including joint venture(s), if any, in the month of March of a year, is equal to or more than the reporting threshold;
- (ll) “reporting threshold” means one lakh or as may be prescribed by the Authority by a direction or an order from time to time;

- (mm) “set top box” or “STB” means a device, which is connected to or is part of a television receiver and which enables a subscriber to view subscribed channels;
- (nn) “subscriber” for the purpose of these regulations, means a person who receives broadcasting services, from a distributor of television channels, at a place indicated by such person without further transmitting it to any other person and who does not cause the signals of television channels to be heard or seen by any person for a specific sum of money to be paid by such person, and each set top box located at such place, for receiving the subscribed broadcasting services, shall constitute one subscriber;
- (oo) “subscriber management system” means a system or device which stores the subscriber records and details with respect to name, address and other information regarding the hardware being utilized by the subscriber, channels or bouquets of channels subscribed by the subscriber, price of such channels or bouquets of channels as defined in the system, the activation or deactivation dates and time for any channel or bouquets of channels, a log of all actions performed on a subscriber’s record, invoices raised on each subscriber and the amounts paid or discount allowed to the subscriber for each billing period;
- (pp) “television channel” means a channel, which has been granted permission for downlinking by the Central Government under the policy guidelines issued or amended by it from time to time and reference to the term ‘channel’ shall be construed as a reference to “television channel”.

(2) All other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act and the rules and regulations made thereunder or the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (No. 7 of 1995) and the rules and regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

CHAPTER- II

PROCEDURE FOR REPORTING OF INFORMATION

3. Reporting of information relating to reference interconnection offers and interconnection agreements by broadcaster and distributor. —

(1) Every broadcaster shall, through its compliance officer, report to the Authority, its RIO and modifications or amendments thereto, simultaneously when the same is published on its website as per regulations 7, of the Interconnection Regulations, in the manner and format as provided for in Schedule-I or as may be prescribed by the Authority by a direction or an order from time to time.

(2) Every distributor shall, through its compliance officer, report to the Authority, its RIO and modifications or amendments thereto, simultaneously when the same is published on its website as per regulations 8, of the Interconnection Regulations, in the manner and format as provided for in Schedule II, or as may be prescribed by the Authority by a direction or an order from time to time.

(3) Every broadcaster shall, through its compliance officer, report to the Authority, the information relating to all interconnection agreements in respect of channels

- (i) for which RIO has been published as per regulations 7, of the Interconnection Regulations
- (ii) for placement,
- (iii) for marketing, or
- (iv) for any other technical or commercial arrangements,

and modifications or amendments thereto, within thirty days from the date of signing of such agreements and modifications or amendments, as the case may be, in three parts, namely, Parts A, B and C, in the manner and format as provided for in Schedule-III or as may be prescribed by the Authority by a direction or an order from time to time.

Provided that the information related to all such existing agreements, signed up to the date of commencement of these regulations, shall be reported within thirty days from the date of commencement of these regulations.

(4) Every reporting distributor shall, through its compliance officer, report to the Authority, the information relating to all interconnection agreements for which RIO has been published as per regulations 8, of the Interconnection Regulations, and modifications or amendments thereto, within thirty days from the date of signing of such agreements and modifications or amendments, as the case may be, in the manner and format as provided for in Schedule-IV or as may be prescribed by the Authority by a direction or an order from time to time.

Provided that information related to all such existing agreements, signed up to the date of commencement of these regulations, shall be reported within thirty days from the date of commencement of these regulations.

Provided further that in cases where the average active subscriber base of its entire distribution network, including joint venture(s), if any, of a distributor, who was a reporting distributor in the preceding year, falls below the reporting threshold, then such distributor shall, within thirty days from the end of March of the respective year, furnish to the Authority, a certificate to that effect, duly signed by its compliance officer.

(5) Every reporting distributor shall, through its compliance officer, report to the Authority, the information relating to all interconnection agreements and modifications or amendments thereto, signed with LCOs, within thirty days from the date of signing of such agreements and modifications or amendments, as the case may be, in the manner and format as provided for in Schedule-V or as may be prescribed by the Authority by a direction or an order from time to time.

Provided that information related to all such existing agreements, signed up to date of commencement of these regulations, shall be reported within thirty days from the date of commencement of these regulations.

(6) Every reporting distributor shall, through its compliance officer, verify the information filed by the broadcaster, under sub regulation (3), in respect of all interconnection agreements and modifications or amendments thereto, signed between them, within fifteen days from the date of filing by the broadcaster, in the manner as may be prescribed by the Authority by a direction or an order from time to time.

Provided that if a broadcaster fails to file the information in respect of such agreements and modifications or amendments thereto, then the concerned reporting distributor shall report to the Authority, the information relating to the same, within forty five days from the date of signing of such agreements and modifications or amendments, as the case may be.

(7) Every broadcaster shall, through its compliance officer, verify the information filed by the reporting distributor, under sub regulation (4), in respect of all interconnection agreements and modifications or amendments thereto, signed between them, within fifteen days from the date of filing by the reporting distributor, in the manner as may be prescribed by the Authority by a direction or an order from time to time.

Provided that if a reporting distributor fails to file the information in respect of any such agreements and modifications or amendments thereto, then the concerned broadcaster shall report to the Authority, the information relating to the same, within forty five days from the date of signing of such agreements and modifications or amendments, as the case may be.

(8) Every broadcaster and reporting distributor shall, within thirty days from the end of March of every year, also furnish to the Authority a certificate, duly signed by its compliance officer, to the effect that to the best of their knowledge, all the requisite information related to all the interconnection agreements and modifications or amendments thereto, liable to be reported within the preceding financial year, have been reported, and all the information submitted is true, correct and complete in all respects.

4. Consequences for failure to report or verify the reported information by the broadcaster or distributor.—

(1) If any broadcaster or distributor fails to furnish the information or certificate or fails to verify the reported information, as required under regulation 3, by the due date, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its license/permission/registration, or the Act or rules or regulations or order made or direction issued thereunder, be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of rupees one thousand per day for default up to thirty days beyond the due date and an additional amount of rupees two

thousand per day in case the default continues beyond thirty days from the due date, as the Authority may, by order, direct.

Provided that the financial disincentive levied by the Authority under this sub-regulation shall in no case exceed Rupees Two Lakhs.

Provided further that no order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the Authority unless the broadcaster or the distributor, as the case may be, has been given a reasonable opportunity of representation against the contravention of the regulations observed by the Authority.

(2) The amount payable by way of financial disincentive under these regulations shall be remitted to such head of account as may be specified by the Authority.

CHAPTER- III

PROCEDURE FOR MAINTENANCE OF REGISTER AND ITS INSPECTION

5. Maintenance of the register.— The Authority shall maintain the register in two parts, namely Part I and Part II where:

(i) Part I shall consist of the information

- (a) as reported under sub-regulations (1), (2), (4) and (5) of regulation 3; and
- (b) as reported in Part A under sub-regulation (3) of regulation 3;

(ii) Part II shall consist of the information as reported in Parts B and C under sub-regulation (3) of regulation 3.

6. Inspection of the register.— (1) The register shall be treated as non-confidential, unless a party to an interconnection agreement requests the Authority, in the manner and format prescribed in sub-regulation (2) hereunder, to keep any part of the agreement reported in Part II as confidential.

(2) The request for confidentiality as per sub-regulation (1) above, shall be made in writing, along with a non-confidential summary of the portion sought to be kept confidential. The service provider shall clearly indicate the paras or parts thereof that may be treated as confidential. Such a request shall be accompanied by reason(s) for keeping such information as confidential.

(3) Where the Authority proposes to reject the request for confidentiality, it shall inform the service provider, in writing, the reasons for doing so, and give an opportunity to make a representation against the same within a stipulated period. On consideration of such representation, if any, the Authority shall take a final decision. In case the Authority rejects the request of the service provider, it shall communicate the same, in writing, along with the reasons for doing so.

(4) Subject to the provisions contained in sub-regulations (1) to (3) above, the non-confidential part (s) of the register shall be kept open for inspection to any member of public on payment of fee prescribed under sub-regulation (7) hereunder.

(5) Any person seeking inspection of the register shall apply, in writing, to the officer designated for the purpose by the Authority, giving details of the information sought.

(6) The designated officer shall allow inspection of the register and also make available extracts of the relevant portions of the register on receipt of the fee prescribed under sub-regulation (7) hereunder.

(7) Levy of fee and other charges:

- (i) A fee of Rs. 50 per hour, or as may be prescribed by the Authority by a direction or an order from time to time, shall be levied for inspection of the register.
- (ii) A fee of Rs. 20 per page, or as may be prescribed by the Authority by a direction or order from time to time, shall be charged for copies of extracts from the register.

Provided that the Authority may provide copies of extracts in soft format with appropriate watermark(s).

- (8) Nothing contained in this regulation shall apply to an interconnection agreement entered in the register—
- (i) in respect of which a period of three years has expired from the date of reporting of such agreement, or
 - (ii) in respect of which the period of validity as specified in the agreement has expired,
- whichever is later.

CHAPTER- IV

MISCELLANEOUS

7. Designation of compliance officer and his/her obligations. — (1) Every broadcaster and distributor shall, within fifteen days from the date of notification of these regulations, designate a compliance officer.

(2) Every broadcaster or distributor, who commences its operations after coming into effect of these regulations, shall, within fifteen days from the date of commencement of its operations, designate a compliance officer.

(3) Every broadcaster and distributor, shall, within fifteen days from the date of designation of the compliance officer under the provisions of this regulation, furnish to the Authority the name, complete address, contact number and e-mail address of the compliance officer along with authenticated copy of -

- (a) the board's resolution in case the service provider is a company; or
- (b) an authorization letter from the competent officer of the service provider in case it is not a company;

authorizing the designation of such compliance officer as provided for in Schedule VI.

(4) In the event of any change in the name of the compliance officer so designated under provisions of this regulation, the same shall be reported to the Authority by the service provider within fifteen days from the date of occurrence of such change along with an authenticated copy of the board's resolution or authorization letter from the competent officer, as the case may be.

(5) In the event of any change in the address or contact number or email address of the compliance officer, the same shall be reported to the Authority by the service provider within fifteen days from the date of occurrence of such change.

(6) The compliance officer shall be responsible for—

- (a) reporting to the Authority, with respect to compliance with these regulations and directions of the Authority issued under these regulations; and
- (b) ensuring that proper procedures have been established and are being followed for compliance of these regulations.

8. Removal of Difficulties. — In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue appropriate clarifications from time to time.

9. Repeal and Saving. — (1) The Register of Interconnect Agreement (Broadcasting and Cable Services) Regulation, 2004 (No. 15 of 2004), dated 31st December, 2004, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of regulation mentioned under sub-regulation (1), anything done or any action taken or proposed to have been done or taken under the said regulation shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these regulations.

U K SRIVASTAVA, Secy. Incharge, TRAI

[ADVT. – III/4/Ext./197/19]

Note: The Explanatory Memorandum annexed herewith explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Register of Interconnection Agreements and all such other matters Regulations, 2019.

The Explanatory Memorandum to the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Register of Interconnection Agreements and all such other matters Regulations, 2019 (No. 02 of 2019)

Background

1. The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (the TRAI Act) entrusts the Authority, amongst others, the functions to ensure technical compatibility and effective interconnection between different service providers, fix the terms and conditions of interconnectivity as well as regulate arrangement amongst service providers for sharing their revenue. Broadcasting and Cable Services were brought within the ambit of telecommunication services in terms of section 2(k) of the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 in the year 2004 vide the notification number 39 (S.O.44(E) and 45 (E)) of 2004.
2. The interconnection between service providers is a technical or commercial or a combination of technical and commercial arrangement under which service providers connect their equipment and networks to enable subscribers to have access to the services. Accordingly, the Authority had put in place regulatory framework for interconnection by making the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulations, 2004 dated 10th December 2004 and the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable TV Systems) Regulations, 2012 dated 30th April 2012. Based on this framework the broadcaster or distributor of television channels finalize the commercial and technical terms and conditions to arrive at an agreement. Under the existing interconnection regulatory framework broadcasters are required to provide the signals of TV channels to the distributors of TV channels on non-discriminatory terms. Similarly, distributors of television channels are also required to provide access to their networks to the broadcasters on non-discriminatory terms.
3. Section 11 (1) (b) of the TRAI Act, 1997 mandates the Authority to maintain register of interconnection agreements and keep it open for inspection. The said provisions are reproduced below:

“11 (1) (b)-----

vii. Maintain register of inter-connect agreements and of all such other matters as may be provided in the regulations;

viii. Keep register maintained under clause (vii) open for inspection to any member of public on payment of such fee and compliance of such other requirements as may be provided in the regulations;

ix.-----”
4. Keeping in view the aforesaid provisions of the TRAI Act and the regulatory framework for interconnection, the Authority notified separate regulations namely, “The Register of Interconnect Agreements (Broadcasting and Cable Services) Regulation 2004” (15 of 2004) on 31.12.2004, (herein after referred as the Register of interconnection regulations) which prescribe modalities for the maintenance of the Register of Interconnection Agreements for broadcasting and cable services. The said regulations were amended from time to time, in line with changes in interconnection regulations.
5. As per Register of interconnection regulations, the broadcasters were required to report the details of the interconnection agreements signed with the distributors of TV channels on annual basis. Similarly, the DTH operators, HITS operators and IPTV operators were required to report their interconnection agreements signed with broadcaster on annual basis. A direction dated 29th July 2009 was issued to the broadcasters directing them to report the details of interconnection agreements in electronic form (in non-writable CDs) along with its print form. A direction dated 29th July 2009 was issued to DTH, HITS and IPTV operator to furnish copy of each interconnection agreement with the Authority and also to furnish the details of interconnection agreements in electronic form. The register of interconnect agreements was to be maintained in two parts: part A and part B wherein part A was kept open for inspection by any member of public on payment of prescribed fee and part B was not open for the public inspection. Part B contained information which was decided by Authority on request of service

provider to be kept confidential. While deciding the confidentiality of the information, the Authority was required to follow the relevant provisions of the Telecom Regulatory Authority of India (Access to Information) Regulation, 2005. The Telecom Regulatory Authority of India (Access to Information) Regulation, 2005 has a provision for exemption of following information from disclosure:

- (i) trade and commercial secrets and information protected by law;
- (ii) Commercially and financially sensitive information, the disclosure of which is likely to cause unfair gain or unfair loss to the service provider, or to compromise his competitive position.

6. On examination of the interconnection filing/details made by the broadcaster or distributor of television channels under Register Regulation, 2004, the Authority had, inter-alia, observed that:

- a) There was a lack of uniformity in filings received from various broadcaster or distributor of television channels;
- b) There were varied interpretations of the requirement in the Register Regulation, 2004 regarding filing of standard affiliation agreement;
- c) Reporting of information in print form became a time-consuming and laborious task and was also not eco-friendly.

Therefore, review of the Register Regulation, 2004 was expedient.

7. In line with the established practice, for reviewing the regulatory framework for register of interconnection agreements, the Authority issued a consultation paper titled as “the Register of Interconnection Agreements (Broadcasting and Cable Services) Regulations, 2016” on 23rd March 2016. In response to the said consultation paper, a total of 26 comments & 2 counter-comments were received from stakeholders. Subsequently, an Open House Discussion (OHD) was held on 26th May 2016 in Delhi, which was attended by a large number of stakeholders.

8. Meanwhile, the Authority notified a new regulatory framework on 3rd March 2017, which is uniform for all types of addressable systems. The said framework comprises of the following regulations and Tariff Order.

- a. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 [*hereinafter referred as Interconnection Regulations, 2017*]
- b. The Telecommunication (Broadcasting and cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 [*hereinafter referred as QoS Regulations, 2017*]
- c. Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017 [*hereinafter referred as Tariff Order, 2017*]

9. The new regulatory framework was notified in March 2017. However, pursuant to a legal challenge to the said regulations, the regulations have come into effect from 3rd July 2018 after satisfying legal issues. Hon’ble Supreme Court has since upheld the powers of TRAI vide its order dated 30.10.2018 and adjudicated that the Regulations and Tariff Order are intra vires the TRAI Act. Some Service Providers have also challenged the Regulations and Tariff Order at the High Court of Delhi. After the coming into effect of the new regulatory framework, all the service providers are required to enter into the interconnection agreement in accordance with the said framework; consequently, the reporting requirements under these regulations are dependent upon the parameters prescribed by the new framework. The salient features of the new regulatory framework are given below:

- a) Every broadcaster is required to declare the maximum retail price (MRP) of its pay channels on a-la-carte basis. However, such MRP shall be uniform for all types of addressable systems.
- b) Every Broadcaster must declare a distribution fee at a minimum of 20% of the MRP of pay channel or bouquet of pay channels which can be upto 35%
- c) In addition to the distribution fee, Broadcasters may offer discounts to distributors which cannot exceed 15% of the MRP of pay channels or bouquet of pay channels. However, in no case, the

sum of distribution fee declared by a broadcaster and discounts offered can exceed 35% of the MRP of pay channel or bouquet of pay channels, as the case may be.

- d) Every broadcaster should publish, on its website, the Reference Interconnection Offer (RIO) containing the information such as MRP of its pay channels and bouquet of pay channels, distribution fee, discounts etc. and provide a copy simultaneously to the Authority.
- e) Every broadcaster is required to enter into written interconnection agreements on the basis of the RIO published by it for providing signals of pay channels to a distributor of television channels.
- f) Similarly, every distributor of television channels is required to publish RIO on its website for carrying a channel on its distribution network. Such RIO must necessarily contain the information such as target market, rate of carriage fee, manner of calculation of carriage fee etc. and provide a copy simultaneously to the Authority.
- g) The rate of carriage fee has been capped at Re. 0.20 per Standard Definition channel and Re. 0.40 per High Definition Channel. The manner of carriage calculation is as prescribed in the regulations. The distributor can offer a discount on the carriage fee. However, such discount cannot be more than 35%.
- h) Every distributor is required to enter into written agreement, on the basis of its published RIO, with the broadcaster for carrying television channels in respect of which the request has been received from such broadcasters.
- i) Any other kind of fee for a channel such as marketing fee, placement fee etc, between two service providers should be made part of interconnection agreement and reported to the Authority.
- j) Some distributors (for example Multi-Service Operators) provide the Broadcasting Service through LCOs. For such distributors it is mandatory to enter into a written agreement before providing the signals. Such interconnection agreement must comply with the standard provisions as per the Model Interconnection Agreement (MIA)/Standard Interconnection Agreement(SIA) as prescribed by the Authority.

Disclaimer: The salient points as above are for general explanation only and have no bearing on the relevant clause(s) in the regulations.

10. Based on the comments received in the consultation process and analysis of the developments in the market pursuant to implementation of the new regulatory framework draft Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Register of Interconnection Agreements Regulations, 2019 was issued by TRAI on 22nd April 2019. Written comments on these draft Regulations were invited from all stakeholders by 6th May 2019. In view of requests by some stakeholders, the last date for submission of written comments was extended upto 13th May, 2019 and counter comments were invited by 20th May 2019. In response to the said consultation paper, a total of 21 comments were received from stakeholders. Subsequently, an Open House Discussion (OHD) was held on 10th June 2019 in Delhi. A large number of stakeholders attended the Open House Discussion.
11. The following paragraphs provide gist of the comments/views of the stakeholders received on the issues, analysis of these comments and objects & reasons of these regulations.

Reporting requirements relating to interconnection agreements

12. The value chain in the distribution of television channels comprises of the broadcaster, the distributor of television channels, the local cable operator and the end subscriber. The business of distribution of television channels from the broadcaster to the subscriber has two levels – i) the broadcaster provides the signals of television channels to distributor of television channels and ii) the distributor of television channels offers these channels, either directly or through local cable operator, to the subscribers. Amongst the distributor of television channels, DTH operator serves the subscriber directly, while MSO and the HITS operator generally serve the subscribers through its linked LCOs. Thus, in the business process of provisioning of television channels, television signals flow from the broadcasters to the subscriber via the distributors of television channels. However, a broadcaster or distributor of television channels in the value chain may act as a seeker or as a provider. For example, when a distributor seeks

signals of TV channels from a broadcaster, it acts as a seeker and the broadcaster in such case becomes a provider of the signals of TV channel. Similarly, when a broadcaster approaches a distributor requesting the distributor to carry its TV channels on the distributor's network then it acts as a seeker and the distributor becomes a provider of access to the network.

13. Therefore, in the consultation paper it was envisaged that the provider of television signals or access to the network, as the case may be, should be made responsible for furnishing the information relating to the interconnection agreements to the Authority. Accordingly, it was proposed in the consultation paper that the details of interconnect agreements between broadcaster of pay channel and distributor of TV channels shall be reported by the broadcaster of pay channel. Similarly, the interconnect details between distributor and LCO shall be reported by the distributor. Further, the carriage details wherever applicable shall be reported by the distributors.
14. As per interconnection regulation 7, every broadcaster is required to submit a copy of their reference interconnection offer, for the purpose of record, to the Authority. Further any amendments thereto are to be reported as per sub clause 7(8) of interconnection regulation. As per interconnection regulation 8, every distributor of television channels is to submit a copy of their reference interconnection offer for the purpose of record to the Authority. Further any amendments thereto are to be reported as per sub clause 8(7) of interconnection regulation. Irrespective of the size of the distributor, all the distributors are required to report their RIO.
15. During the consultation process, one stakeholder commented that the carriage fee/placement fee agreements are not interconnect agreement. Therefore, there should not be any requirement to report the carriage fee/placement fee. Some stakeholders commented that in order to ensure complete transparency and non-discrimination, the parties should be directed to submit all the agreements with any kind of compensation (in monetary terms or otherwise¹), whether carriage / marketing / support or any other tag, signed among them. During the consultation process related to draft Regulation, many stakeholders opined that the reporting requirements under the Draft Regulations should restrict to subscription, carriage/placement RIOs. Inclusion of any other commercial arrangements between broadcasters and DPOs would result in expansion of scope of the regulations. Few stakeholders favoured that details of all the agreements including any incentive (monetary or otherwise) for marketing or support or visibility or placement signed between Broadcaster and distributor of television channels should be reported. Some stakeholders have submitted that the prevalence of placement agreement, that are under forbearance, is vitiating the whole regime. As per them many Distributors are misusing the available flexibility to arm-twist the broadcasters. One of the stakeholders also opined that a level playing field may not be ensured for a Broadcaster, since the Distributor is at liberty to fix varied Marketing Fees from different Broadcasters or he may even exempt it from a few Broadcasters. This is blatant violation of the new regime which aims at creating a level playing, fair play and non-discriminatory approach.
16. The 'Interconnection Agreement' by definition (clause 2 (y)) includes all technical and commercial arrangements among the service providers. Therefore, the scope and mandate of this regulation include all technical and commercial arrangements for re-transmission of television channels. Moreover, Section 11(1) (b) (vii) of the Act mandates the Authority to maintain register of interconnect agreements and **of all such other matters** as provided in the Regulations. The interconnection regulations and this regulation endeavour to create a transparent regime to foster a level playing field. The regulation includes sufficient safeguards for maintaining the confidentiality of information. The regulation accords opportunity to service providers to claim confidentiality of commercially important information. Seeking information by the regulator does not in any way curtail the freedom of market participants. The Act empowers the Authority to call for any information including all technical and commercial arrangements.
17. Transparency and non-discrimination are core principles of the interconnection regulations. All the consequential agreements (consequential to the Interconnection agreement) between the service providers should comply with the principle of Transparency and non-discrimination. Such subsequent

¹ For example: an agreement without any direct monetary benefits, but providing or availing assured advertisement slots or assured LCN number etc.

agreements should not alter the nature and form of mandatory technical and commercial conditions of the interconnection agreements. Vis-à-vis these agreements (Placement fee, marketing fee or any other nomenclature of mutual agreement among service providers), the Authority has followed a principle of light touch regulatory regime, whereby no ceiling or formula has been prescribed. However, as a sector regulator it is important for the Authority to be aware of the types and commercial implications of such arrangements/ agreements for effective oversight. The service providers may be free to enter into such agreement(s); however these must be reported to the Regulator.

18. As per the Interconnection Regulations, 2017, broadcaster is required to enter into written interconnection agreement before providing signals of pay channels to a distributor. Therefore, the Authority decided that obligation of reporting in respect of pay channels shall rest with pay broadcasters as in such case it is acting as provider of signals. Further, in terms of Interconnection Regulations, 2017, it is the responsibility of every distributor of television channels to enter into a written agreement with the broadcaster where the broadcaster has made request to carry its television channels on the network of the distributor. Therefore, in such cases, being the provider of the access of the network, the responsibility of reporting the information relating to such agreements shall rest with the distributor. In case of interconnection agreement between distributor of television channels and LCO wherever applicable, the information shall be reported by the distributor since the distributor is the provider of signals to the LCOs. Accordingly, necessary provisions have been incorporated in the regulations.
19. As regards the placement agreement, the Authority noted that as per the extant regulatory framework, the broadcaster may offer discount within the prescribed limit or pay the mutually agreed fee, after signing the interconnection agreement, to a distributor for placing the channel at the desired position in the EPG. It is important to note here that such agreements and any other individual agreements are required to be filed with the Authority. The Authority is of the view that the details of all other individual agreements which include marketing, placement, agreements on advertisement slots, extended credit facility, etc. should be reported to the Authority by the Broadcasters. Also, the marketing fee details and for that matter any kind of fee for a channel, between broadcaster and distributor shall be reported to the Authority. Thus, any incentive (monetary or otherwise) for marketing or support or visibility or placement signed between Broadcaster and distributor of television channels shall be reported to the Authority by the broadcaster.
20. In addition to reporting their RIO, the broadcasters will be reporting the details of information of the individual agreements signed with distributor of television channels, as per RIO. Further, the broadcasters will also be reporting the details of all other individual agreements signed with distributor of television channels. Any deviation in RIO based agreements also needs to be reported under Regulation 3(3) of this Regulation. Accordingly, necessary provisions have been incorporated in the regulations.
21. The Draft regulations prescribed that the Compliance officer designated as per the provisions of The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) may by default be designated compliance officer under the Register of Interconnection Agreements regulations too. During the consultation on Draft Regulations, few stakeholders commented that given their organization structure the Regulatory Compliance officer under other regulations does not handle interconnection agreements. Therefore, these stakeholders commented that the service provider should be provided with the freedom to designate separate compliance officer under these regulations. The Authority has duly considered the suggestion and accordingly the relevant provisions have been duly modified. As per the regulation, every broadcaster or the distributor of television channels is required to designate a compliance officer, within fifteen days from the date of notification of these regulations. The broadcasters and distributors of television channels are required to report the name /details of compliance officer on the service provider portal [www.spp.trai.gov.in]² hosted by the Authority on its website www.trai.gov.in, within fifteen days from the date of issue of this Regulation.

Exemption from reporting the interconnection details

² or as prescribed from time to time.

22. In the consultation paper, it was proposed that Authority may exempt certain class of service providers from reporting information relating to interconnect agreements. On this issue, some stakeholders stated that any exemption provided by the Authority should be transparent and should be made equally applicable. During the consultation process related to draft Regulation, many stakeholders advocated that exemptions should not be given to any MSOs.
23. The Authority observes that there are 1143³ active MSOs and approximately 100,000 LCOs working in the industry. As per the data available from MIB, there are 1061 active MSOs with subscriber base of less than one lakh subscribers. It has been observed that many MSOs are small players providing service in remote rural areas or in small towns catering to small number of subscribers. Also, since the digitisation of cable TV has been completed in India in March 2017 only, therefore, some of the MSOs are at the nascent stage of operations in digital addressable distribution platform. Such small MSOs may have capacity constraints both in terms of manpower as well as financial. Therefore, initially, it may be appropriate to seek information, only from those distributors who have a significant subscriber base. Further, as per the information available from MIB, MSOs with one lakh or more subscriber base cover more than 85% of subscribers base. Accordingly, it has been decided by the Authority that only distributors, having average active subscriber base of one lakh or more in the month of March of a year, shall be under obligation to report the information relating to their interconnection agreements (let us say a distributor has average active subscriber base of 1,00,000 subscribers in March 2019 then it would report the interconnection details in respect of all the agreements. However, all the DPOs shall report their carriage RIO (i.e. RIO published by the distributor of television channel as per Regulation 8 of Interconnection Regulation 2017) to the Authority. The average active subscriber base for the month of March will be calculated as prescribed in Interconnection Regulations, 2017. For a distributor having multiple head-ends, the calculation shall include the subscribers of all the distribution networks including those of all the head-ends operated by him.
24. There are few MSO's who are operating different companies as Joint Ventures. In case any MSO or any of its JV partner becomes eligible to report for the register of interconnection i.e. becomes 'reporting distributor' then all its joint venture partners/ associate companies working as distributors must submit the interconnection agreements.
25. Further, these regulations provide that if any distributor once crosses the reporting threshold then it will attain the status of "reporting distributor". Afterwards, if the subscriber base of any reporting distributor, falls below threshold in any of the subsequent years, it shall furnish a certificate duly signed by compliance officer to the Authority that its subscriber base is below the threshold for that year.
26. In cases where the average active subscriber base of the entire distribution network of a distributor, who has not been under obligation to file the report under this sub-regulation, reaches above one Lakh (One hundred Thousand) in the month of March of any of the subsequent years, then such distributor is required to file the report under this sub-regulation for all the Interconnection agreements from the month of March of that year. The distributors are required to explicitly state whether their average active subscriber base is greater or less than one lakh
27. As such, the distributor having average active subscriber base below the reporting threshold have been exempted from the obligation of reporting details of interconnection agreements. Such distributors shall report their carriage RIO to the Authority. This exemption is in line with promoting ease of business and reducing regulatory burden on MSOs with subscriber base below a threshold and with limited resources. However, such distributors are also encouraged to report the information voluntarily so that the holistic data of the industry is available in the Register. This will help the Authority in better monitoring of the industry and to take suitable measures/ decisions for the orderly growth of the industry. The Authority is in the process of developing an online portal for submission of reporting under this Regulation, the Authority may mandate MSOs with average active subscriber base of less than one lakh to also report the details of their Interconnection agreements in future. The reporting threshold of one lakh subscribers will be reviewed by the Authority from time to time.

Periodicity of reporting

³ As per information received from MIB on January 20, 2019.

28. Initially, when the Register Regulation 2004 was notified on 31st December 2004, it had the provision for quarterly reporting of the information. But in the year 2009, this provision was revised for annual reporting. The consultation paper espoused for monthly reporting, wherein the service provider would need to report the information about all its agreements signed during a month, within 10 days from the end of that month.
29. On this issue, some stakeholders commented that the periodicity of the report should continue to be once in a year only. It has been suggested that at best the periodicity can be changed to twice a year for all service providers as there is considerable increase in the number of distributors of television channels. Further that the information is quite dynamic with frequent launching of new channels by the broadcasters, amendments or addendums etc. Updating the data on monthly or quarterly basis will be extremely cumbersome and a tedious exercise. Few stakeholders suggested that the service providers should report the details of their interconnection agreements on quarterly basis. One of the stakeholders commented that if during a quarter, no agreement is signed then the service provider should furnish a blank submission stating that no agreements executed during that quarter. Some other stakeholders agreed with the monthly reporting of interconnection agreements as proposed in the draft regulations during consultation. According to them, as soon as interconnection agreements are signed, the information about such agreements should be reported to TRAI without any delay or manipulations.
30. The Authority noted that the industry practice is largely to sign interconnection agreements on yearly basis. Since, the periodicity of the reporting under previous regulations was also once in a year, sometimes when these agreements were reported, their validity was already over. Therefore, in such cases, it was not feasible to take any corrective action even if it was necessary. Keeping in view of the experience, the Authority observed that the reporting of information relating to interconnection agreements should be within a reasonable time after its execution for effective implementation of the principles of non-discrimination and monitoring. There is a requirement to create a balance between the necessary oversight by regulator vis-a-vis the compliance burden on stakeholders. Accordingly, the Authority having considered various comments, market information and its own analysis has decided that information relating to interconnection agreements shall be reported within thirty days from the date of signing of such agreements or modifications or amendments or addenda, as the case may be. The Authority is of the view that reporting details of an agreement within thirty days from its date of signing will not create any additional burden on the broadcasters and DPOs as one agreement is required to be reported only once. Once an agreement is reported it is not required to be reported again unless it has been amended. In such a case only, the amendment is required to be reported within thirty days of signing of such amendment. Thus, one agreement or any amendment to an agreement is required to be reported only once. Therefore, there is no extra burden on any broadcaster or a distributor. In fact, such a reporting balances and spreads the reporting evenly across the year, instead of a largescale reporting of all the 100 % agreements or amendments thereof in one stroke.
31. The broadcaster or reporting distributor shall report to the Authority about the details of all their interconnection agreements within thirty days from the date of signing of such agreements or modifications or amendments or addenda, as the case may be. The Authority is of view that in order to avoid duplication of reporting, once a particular agreement is reported with TRAI then the same should not be reported again until any change/ modification is made in such agreement. Such change or amendment should also be reported within 30 days from date of signing of such amendment or modification. A new broadcaster also shall report the information relating to interconnection agreements within thirty days from the date of signing of such agreements or modifications or amendments or addenda, as the case may be.
32. The reporting distributor of television channels shall verify the information filed by the broadcaster in respect of all individual agreements signed amongst them, within fifteen days from the date of filing by the Broadcaster. Similarly, the concerned broadcaster shall verify the information filed by the reporting distributor in respect of all individual agreements signed amongst them, within fifteen days from the date of filing by the reporting distributor. The Authority will endeavour to generate system enabled email to the concerned compliance officer to prompt such verification.
33. In case a broadcaster/reporting distributor fails to file the information in respect of any agreement then the concerned reporting distributor /broadcaster shall inform and report to the Authority, the

information relating to all the interconnection agreements within forty five days from the date of signing of such agreements or modifications or amendments or addenda, as the case may be.

Mode and Format of reporting

34. As regards the mode of reporting, all the stakeholders are in-agreement with the electronic mode as proposed in the consultation paper. The Authority noted that information relating to interconnection agreements being voluminous in nature, it will be in the interest of the broadcaster or distributor of television channels that such information is reported through electronic means. It will also be easy to retrieve and manage such information by the Authority and the stakeholders. There may be various alternatives for reporting the information in electronic mode like CD-ROM, e-filing through emails or by uploading the e-documents or information related to Interconnection agreements on the website/e-portal. The Authority would separately specify the mode of e-reporting through suitable direction(s).
35. During consultation, comments were sought from the stakeholders on the formats of reporting as proposed in the draft regulations. In addition to the formats, the requirement of filing of the copies of actual agreements was also proposed. Stakeholders have given divergent views on these formats. Also, the parameters mentioned in the formats/tables were according to the previous interconnection regulatory framework which has now been replaced by the new framework therefore some of the suggestions of stakeholder may not be relevant in the present context. On the issue of filing of actual copies of agreements, some stakeholders have suggested to remove the requirement of filing copies of agreements while some other stakeholders have pressed for mandating the service providers to file the copies of their actual agreements so that the tabular details provided by them may be cross-checked. Majority of the MSOs have suggested that they may be exempted from filing the copies of their interconnection agreements signed with LCOs as such agreements have already been pre-defined by TRAI in the form of Model Interconnection Agreement (MIA) and Standard Interconnection Agreement (SIA).
36. It was noted by the Authority that the formats of reports may require changes over a period depending on the changes in interconnection framework and other relevant requirements. The Authority has prescribed the broad headings/parameters under which a broadcaster or distributor of television channels shall furnish the information in Schedules of this Regulation. The specific format in line with the regulatory framework in vogue may be prescribed by the Authority through suitable direction from time to time. This methodology will obviate the need of amendments to the regulations. This will also enable the Authority to seek most appropriate information/dataset as deemed necessary.
37. The details of information required to be reported by the broadcaster of individual agreements signed with distributor of television channels including those, as per reference interconnect offer are mentioned in Regulation 3(3). The reference interconnect offer published by the broadcaster is available in public domain. Thus all the interconnection agreements signed as per RIO are non-confidential in nature. Similarly, the details of information required to be reported by the distributor of television channels with average active subscriber of equal to or more than one lakh, of individual agreements signed with Broadcaster, as per reference interconnect offer are mentioned in Regulation 3(4). The reference interconnect offer published by the distributor is also available in public domain. Thus, all the interconnection agreements signed as per RIO are non-confidential in nature. The regulation mandate that the information related to all other individual agreements signed with distributor of television channels such as placement, marketing or for any other technical or commercial arrangements shall be reported by the broadcasters in three parts- Part A, Part B and Part C. Part A shall contain certain basic details of each individual agreement/modification /amendment or addendum thereto such as name and address of contracting parties, date of signing of agreement, validity period of agreement, etc. Part B shall contain commercial details in tabular form, as prescribed. Part C shall contain the actual copy, in electronic format, of such agreement/modification/amendment or addendum thereto. The Authority may prescribe a format and an e-form to file the information under this regulation. The Authority may prescribe that digitally signed or scanned copy of agreement in Part C or RIO may be submitted. Regarding RIO based agreements, it may be noted that since they are non-confidential in nature, as explained above therefore the entire information will be captured in Part A only. The Authority would separately specify the mode of e-reporting and the procedure for filing the details of interconnection agreements with the Authority through suitable direction(s).

38. The Authority has accepted the suggestion of stakeholders that the distributors should not be mandated to file the copies of agreements signed with LCOs. Distributor-LCO agreements are standardized as the regulations prescribe for signing of such agreements on MIA/SIA. The distributors have been exempted from filing the copies of actual agreements signed with LCOs. The MSOs are required to report the details of all individual agreements signed with LCOs such as names and addresses of contracting parties, date of signing of the agreement, validity period of the agreement, and area covered by the agreement; the indication, in respect of each of the individual agreements, as to whether the agreement has been signed on the basis of Standard Interconnection Agreement or Model Interconnection Agreement, settlement of service charges (in case of Model Interconnection Agreement) details of revenue share (discounts if any) agreed, if any, and any other details which may be specified by the Authority, through direction, from time to time;
39. Some of the information required to be filed may be in form of tabular details in the format prescribed by the Authority through direction(s) and the copy of interconnection agreement may be the scanned copy of the written agreement in non-editable PDF format or in any other format which the Authority may prescribe through direction(s) from time to time. Filing of copies of actual agreements between the broadcaster and distributor is necessary. It will help the Authority to have a comprehensive and complete data including the terms and conditions of the interconnection agreement and other matters between the broadcaster and distributor of television channels.

Accuracy and Authenticity of reports

40. To ensure accuracy and authenticity, the consultation paper envisioned mandatory affixing of the digital signatures on the documents.
41. As mentioned earlier, the Authority is in the process of developing an online portal for submission of reporting under this Regulation. This portal is endeavoured to have user (i.e. broadcaster and DPO) authentication and each user will have password to report the data. Thus, only authorised person(s) may submit the filings to the Authority. Thus, the Authority is of the view that mandatory filing of only digitally signed documents may not be enforced as of now. Therefore, the submissions under Part C, wherein a copy of the agreement is required to be submitted, could be either a digitally signed document or a scanned document (i.e. scanned copy of actual signed document).
42. The regulation engenders prescription of the format and manner of reporting of the information through direction(s). The relevant direction(s) may also include appropriate clause(s) as regards the digital signatures. Further in order to ensure that the information is complete and correct in all respect, the Authority has mandated that the concerned stakeholders (the other party) shall verify the information filed by the broadcaster/reporting distributor (the first party), in respect of all individual agreements signed amongst them, within fifteen days from the date of filing by the reporting distributor/Broadcaster.

Financial Disincentive for delay in reporting

43. On several occasions it has been noticed that the broadcaster or distributor of television channels do not submit the requisite information within the stipulated time. Stakeholders will appreciate that time-bound compliance is essence of any regulatory regime. Many stakeholders observed that the prevailing regime did not include appropriate clauses that deter late filing. Based on comments and discussions it emerged that some disincentive on late submissions is necessary to improve adherence of timelines. Therefore the Authority has prescribed levying of financial disincentives on the broadcaster or distributor of television channels for delay in reporting. The financial disincentive is proposed on a graded scales. That is if the information is not reported by the due date, then the broadcaster or distributor of television channels will be liable to pay an amount of rupees one thousand per day for the delay of first thirty days. In case of delay beyond thirty days, the financial disincentive will increase and will be @Rs. 2000/- per additional day beyond first thirty days. Therefore in case a broadcaster or distributor of television channels files an information 40 days after the due days, the financial disincentive shall be calculated as under:

a. Example: Calculation of Financial Disincentive for delay of 40 days:

Financial disincentive for first 30 days = Rs. 30000/- (@1000 *30)

Financial disincentive for next 10 days= Rs. 20000/- [@2000*(40-30)]

Total Financial Disincentive = Rs. 50000/-

44. In addition, the authority considers that the maximum financial disincentive may be restricted to an upper limit. Therefore, the authority has prescribed a maximum limit of Rs Two Lakhs (Rs. Two Hundred Thousand only) only. The maximum limit is applicable for each requisite submission and each of the due date as prescribed in the regulations. To re-iterate, the financial disincentive will be calculated distinctly for mandatory filing with respect to each RIO/agreement or other matters as applicable.
45. In case both the broadcaster and a reporting distributor of television channel fail to report any agreement then in addition to the financial disincentive on both such broadcaster and a reporting distributor, the Authority may take suitable action against such erring service providers as per the provisions of TRAI Act. Thus, imposition of any financial disincentive by the Authority on the broadcaster or distributor of television channels for its failure to furnish any information, in no way should be considered as the discharge of liability of broadcaster or distributor of television channels from reporting such information. The Authority retains the right to take suitable action, besides imposing financial disincentive, against a defaulting broadcaster or distributor of television channels and its compliance officer as per the provisions of the TRAI Act, 1997.

Maintenance of Register and Accessibility of information

46. During the consultation process, it was specifically asked by the Authority from the stakeholders as to why all the commercial information submitted by the service providers should not be made accessible to the interested stakeholders. On this issue, divergent views from the stakeholders have been received.
47. Some stakeholders suggested that preserving the confidentiality of sensitive commercial information is a vital safeguard in respect of commercial contracts hence it should not be disclosed to any third party. Some broadcasters commented that protection of commercially sensitive information is their fundamental right to trade and profession guaranteed under Article 19(1)(g) of the Constitution. They have further suggested that TRAI should adopt the same procedure which is provided under Regulation 35 of the Competition Commission of India (General) Regulations 2009 for keeping certain information as confidential or non-confidential. Some stakeholders suggested that Authority should itself scrutinize all the interconnection agreements filed by service providers and upon securitizing if the Authority finds any violation of the principle of non-discrimination then Authority should take appropriate action. Some stakeholders suggested that only trend analysis of the information should be disclosed to the public.
48. On the other hand, some stakeholders suggested that the information should be made available only to interested service providers holding a valid licence. Some stakeholders suggested that the true essence of non-discrimination can only be achieved if every type of information is disclosed so that anyone can get the channels on non-discriminatory basis. They are of view that providing access to relevant commercial information will help service providers to engage in interconnection arrangements looking at the data and trends and it will support level playing field and encourage competition based on efficiency and quality of service and effectively it will lead to transparency and non-discrimination.
49. The Authority is of the view that the details of information required to be reported by the broadcaster/distributor of individual agreements signed with distributor/Broadcaster, as per reference interconnect offer are non-confidential in nature as the reference interconnect offer published by the broadcaster/distributor is available in public domain. Thus all the interconnection agreements signed as per RIO are non-confidential in nature.
50. Some stakeholders raised their views as regards the security of their confidentially sensitive information through the digital documents/ scanned agreements. The Authority will endeavour to ensure full data security of such information. The documents/ agreements submitted by the broadcasters and distributors will be stored in encrypted form. Further the digital documents/ scanned documents will normally be stored in offline modes. The Authority will endeavour to take all suitable measures to ensure that the data stored in the register is not accessible unless as specified under the extent provisions of inspection of the Register.

51. The Authority has decided to maintain the register of interconnection agreements in two parts viz. Part I and Part II. Part I shall consist of the information (a) as reported under sub-regulations (1), (2), (4) and (5) of regulation 3; and (b) as reported in Part A under sub-regulation (3) of regulation 3; and Part II shall consist of the information as reported in Parts B and C under sub-regulation (3) of regulation 3. The register shall be treated as non-confidential, unless a party to an interconnection agreement requests the Authority, in the manner and format prescribed in regulation, to keep any part of the agreement reported in Part II as confidential. The request for confidentiality shall be made in writing, along with a non-confidential summary of the portion sought to be kept confidential. The service provider shall clearly indicate the paras or parts thereof that may be treated as confidential. Such a request shall be accompanied by reason(s) for keeping such information as confidential. In case the Authority proposes to reject the request for confidentiality, it shall inform the service provider, in writing, the reasons for doing so, and give an opportunity to make a representation against the same within a stipulated period. On consideration of such representation, if any, the Authority shall take a final decision. In case the Authority rejects the request of the service provider, it shall communicate the same, in writing, along with the reasons for doing so. Thus, subject to the provisions contained in regulations, the register shall be kept open for inspection to any member of public on payment of fee prescribed under the Regulation.

Schedule -I

(Refer sub-regulation (1) of Regulation 3)

Reporting of Reference Interconnect Offer by Broadcasters

Table (IA) (To be reported by all the Broadcasters)		
S.No.	Parameter	Details to be provided
1	Name of the Service Provider	
2	Details of RIO	No. _____ Date: _____ Attach Soft copy of RIO in Word and pdf Format (Both versions to be submitted)

Table (IB) List of Channels (To be reported by All the Broadcasters)						
S.No	Name of Channel	Type of Channel (Pay/FTA)	Genre of channel	Pay Channels*		
				MRP/ month	Discounts, if any, on MRP to DPOs	Distribution fee*

*Information as per regulation 7 of Interconnection regulation 2017

Table (IC) List of Bouquets (To be reported by All the Broadcasters)						
(Total Number of Bouquets ____)						
S.No	Name of Bouquet	No. of channels in	Name of constituent of	MRP/ month of	Discounts, if any, on MRP to	Distribution fee*

		Bouquets	channels in bouquet	bouquet of pay channels	distributors	
*Information as per regulation 7 of Interconnection regulation 2017						

Schedule -II

(Refer sub-regulation (2) of Regulation 3)

Reporting of Reference Interconnect Offer by All the Distributors

Table (IIA)		
S.No.	Parameter	Details to be provided
1	Name of the Service Provider	
2	Type of the distribution platform (MSO/ HITS/ IPTV/ DTH)	
3	Details of RIO	No. _____ Date: _____ Attach Soft copy of RIO in Word and pdf Format (Both versions to be submitted)
4	Channel Carrying Capacity, actual number of channels currently being carried on the platform and Spare channel capacity	Channel carrying capacity _____ Actual no. of channels carried _____ Spare Channel Capacity _____
5	Average Active Subscriber Base (refer sub regulation 2 of regulation 8 and schedule VII of interconnection regulations, 2017)	SD _____ HD _____ Total _____ Number of Pending Request* _____
6	Carriage Fee	Carriage Fee _____ Discount (if any) _____
7	Whether you are a 'Reporting distributor' **	Yes/ No
<p>* Refer sub-regulation (4)(f) of regulation 4 of Interconnection regulation. Please attach the list of pending channels.</p> <p>** For details refer to the definition of reporting Distributor as provided for in regulation 2 (kk).</p>		

Table (IIB) List of Channels*

Sl. No.	Name of Channel	Type of Channel (Pay/FTA)	DRP of Pay Channel	Genre	Channel no. on EPG
* Information as per of Regulation 8 & Regulation 4 of Interconnection Regulation 2017					

Table (IIC) List of Bouquets*
(To be reported by All the Distributors)

Sl. No.	Name of Bouquet	Name of Constituent Channels in the Bouquets	DRP of Bouquet
* Information as per of Regulation 8 & Regulation 4 of Interconnection Regulation 2017			

Table (IID) Target Market*
(To be reported by All the Distributors)

Sl. No.	Head End Location	Details of Target Market	Remarks if any
* Information as per of Regulation 8 & Regulation 4 of Interconnection Regulation 2017			

Schedule -III

(Refer sub-regulation (3) of Regulation 3)

Details of all individual agreements signed with distributor of television channels (DPO) (To be reported by All Broadcasters)**Table (IIIA): Part A (related to RIO based Agreement to be reported by all Broadcasters having Pay Channel(s))**

Sl.No.	Agreement No.	Name of the DPO	Address of the DPO	Date of signing the agreement	Validity period		Area covered	Number of a-la-carte pay channel	Name of a-la-carte pay channel	Name of Bouquet of pay channels	Distribution fee agreed	Amount of discount on maximum retail price (in %)
					From	To						

Agreements for placement, marketing or any other technical or commercial arrangement (To be reported by All Broadcasters)**Table (IIIB): Part A**

Sl.No.	Agreement No.	Type/name/nature of agreement (placement, marketing or any other technical or commercial arrangement)	Name of the DPO	Address of the DPO	Date of signing the agreement	Validity period		Area Covered
						From	To	

Agreements for placement, marketing or any other technical or commercial arrangement (To be reported by All Broadcasters)

Reported by PAN 2024-2025

Table (IIIC)											
	Part A								Part B		Part C
Sl.No	Agreement No.	Type/name/nature of agreement (placement, marketing or any other technical or commercial arrangement)	Name of the DPO	Address of the DPO	Date of signing the agreement	Validity period		Area Covered	For monetary - Amount in Rs	For non-monetary - Details of incentive	Scanned/ Digitally signed Copy of the agreement
						From	To				

Note: Part B and Part C shall be considered for confidentiality subject to the provisions contained in sub-regulations (1) to (3) of regulation 6

Schedule -IV

(Refer sub-regulation (4) of Regulation 3)

(To be Reported by All Reporting Distributors)

<u>Details of all individual agreements signed with broadcasters in respect of which request for re-transmission of television channel has been received</u>														
Sl.No.	Agreement No.	Name of the broadcaster	Address of the broadcaster	Date of signing the agreement	Validity period		Area covered by the agreement	Number of a-la-carte pay and/or FTA channel	Name of channels covered by the agreement	Nature of channels covered by the agreement (pay or FTA)	Name of Bouquet of pay and/or FTA channels	Name of constituent pay and/or FTA channels of each bouquet of pay and/or FTA channels	Carriage fee agreed in respect of the each channel covered by the agreement (in rupee)	Amount of Discount percentage agreed in respect of the channel (% of carriage fee)
					From	To								

Schedule -V

(Refer sub-regulation (5) of Regulation 3)

(To be Reported by All Reporting Distributors)

Details of agreements with Local Cable operator													
Sl.No.	Agreement No.	Name of the LCO	Address of the LCO	Date of signing the agreement	Validity period		Area covered by the agreement	Specify on which basis the agreement has been signed (MIA/SIA)	Settlement of service charges (1)		Discounts	Any other fee (2) agreed	Remarks (3)
					From	To			Share of LCO in Distribution fee (in %)	Share of LCO in Network Capacity fee (in %)			

- 1) Fill this column only when MIA has been signed and the services charges are to be distributed between MSO & LCO in terms of distribution fee and network capacity fee.

- 2) Fill this column only in case of MIA when there is a different arrangement for settlement of service charges between MSO and LCO other than the sharing of distribution fee and network capacity fee.
- 3) Explain the nature of arrangement if settlement of service charges between MSO and LCO is different from sharing of distribution fee and network capacity fee.

Schedule -VI*(Refer sub-regulation (3) of Regulation 7)***Information related to Compliance officer**

S.No.	Parameter	Details
1	Name of the Service Provider	
2	Type of the Service Provider (Broadcaster/MSO/HITS/IPTV/DTH)	
3	Registered address of the Service Provider	
4	Name of the Authorising officer/ Person	
5	Designation of Authorizing Officer/ Person	
6	Contact Details of the Authorizing Officer/ Person	Phone: (O): (M): e-mail:
7	Board Resolution / Authorization Letter Details	No. _____ Date: _____ (Authenticated Scanned Copy to be attached)
8	Whether original nomination/ Change	Original / Change
9	Name of the compliance officer	
10	Contact Details of the Compliance Officer	Phone: (O): (M): e-mail: